04 - अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे लापता लोग

05 - एकात्म मानव दर्शन को साकार कर रही नरेंद्र मोदी सरकार

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 11 फरवरी, 2026

06 - पुलिस ने चोरी का माल किया बरामद, आरोपियों को भेजा जेल

07 - आत्मनिर्भर व विकसित भारत 2047 के संकल्पों को साकार...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 161, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

बांग्लादेश चुनाव : युवा पीढ़ी में भारत विरोधी भावना क्यों है?

सौतिक बिस्वास

ढाका यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एक बार फिर हलचल बढ़ गई। दीवारों और गलियारों में फैली ग़ुस्से, चुटीली और शायराना ग्रैफ़िटी जेन ज़ी के नेतृत्व वाले जुलाई 2024 के उस आंदोलन की गूंज है, जिसने 15 साल सत्ता में रहीं शेख़ हसीना को अपदस्थ कर दिया था। यूनिवर्सिटी में छात्र छोटे-छोटे समूहों में खड़े होकर राजनीति पर बहस करते दिखते हैं। एक बेतरतीब घास वाले मैदान में, ऊपर झूल रहीं लाल लालटेनें चीनी नववर्ष उत्सव का संकेत दे रही हैं।

यह एक छोटा लेकिन अहम संकेत है, ऐसे देश में जहां चीन और भारत दोनों असर बढ़ाने की होड़ में हैं। यहां मौजूद कई लोगों की 12 फ़रवरी को होने वाले चुनाव में बैलट बॉक्स से पहली बार भेंट होगी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख़ हसीना के हटने के कुछ ही दिनों बाद ज़िम्मेदारी संभाली। हसीना अब दिल्ली में रह रही हैं। शेख़ हसीना को 2024 की कठोर कार्रवाई के मामले में उनकी ग़ैर-मौजूदगी में ही कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़, इस हिंसा में क़रीब 1400 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मामले सुरक्षा बलों की कार्रवाई के हैं।

देश की सबसे पुरानी पार्टी, हसीना की अवामी लीग के पास क़रीब 30 फ़ीसदी जनसमर्थन था लेकिन उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, अब उस उदार-मध्यमार्गी जगह को भरने की कोशिश कर रही है। मुख्य इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने छात्र आंदोलन से निकली एक पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन कैंपस के भीतर और बाहर दिखने वाले नारे सिर्फ़ देश के भीतर लोकतंत्र तक सीमित नहीं हैं। इनका रुख़ अब तेज़ी से सीमा के उस पार की ओर भी है। 'ढाका, नॉट दिल्ली' दीवारों पर लिखा हुआ है और साड़ियों पर भी दिखता है, जो कि दक्षिण एशियाई महिलाओं का प्रमुख परिधान है। नौजवानों के बीच 'हेगेमनी' (वर्चस्व) रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा है, जो बांग्लादेश पर भारत के लंबे प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 24 साल के समाजशास्त्र के छात्र मोशर्रफ़ हुसैन कहते हैं, 'युवा पीढ़ी को लगता है कि भारत हमारे देश में कई सालों से दख़ल देता रहा है। ख़ास तौर पर 2014 के चुनाव के बाद, जोकि मूल रूप से एक-दलीय चुनाव था।' बांग्लादेश में लोकतांत्रिक गिरावट में दिल्ली की कथित भूमिका को लेकर नाराज़गी, दरअसल भारत विरोधी भावना में तेज़ बढ़ोतरी की जड़ में है। नतीजा यह है कि भारत-बांग्लादेश रिश्ते, जिन्हें कभी पड़ोसी कूटनीति का आदर्श बताया जाता था, अब दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

लंदन की एसओएएस यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पढ़ाने वाले अविनाश पालीवाल कहते हैं, 'बांग्लादेश में गहरी भारत-विरोधी भावना और भारत के अपने घरेलू राजनीतिक बहसों में पड़ोसी देश के प्रति सख्ती, कई बार खुली दुश्मनी, के चलते दिल्ली को ढाका में मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। कई लोग शेख़ हसीना के आखिरी सालों में उनके बढ़ते तानाशाही रवैये के लिए दिल्ली के समर्थन को ज़िम्मेदार मानते हैं और भारत को एक हावी पड़ोसी के रूप में देखते हैं। वो 2014, 2018 और 2024 के विवादित आम चुनाव और उन पर दिल्ली की 'मंजूरी' की बात करते हैं।

'विश्वासघात' का यह एहसास, लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, सीमा पर हत्याएं, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, व्यापार पर पाबंदियां और भारतीय नेताओं व टीवी स्टूडियो से आने वाली भड़काऊ बयानबाज़ी के साथ मिलकर ज़्यादा हानिकारक धारणा में बदल गया है। यह धारणा है कि भारत बांग्लादेश को एक संप्रभु और बराबरी के देश की तरह नहीं, बल्कि एक आज्ञाकारी पड़ोसी के रूप में देखता है। दिल्ली के उस फ़ैसले ने भी सीमा पार नाराज़गी को बढ़ाया है, जिसमें एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने से रोका गया और बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका ले जाने से इनकार किया गया।

हालांकि भारत ने अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिशें बढ़ा दी हैं। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता ख़ालिदा ज़िया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका गए और इसी मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक़ रहमान से मुलाक़ात की। भारत ने इस्लामी ताक़तों से भी संपर्क के रास्ते खोले हैं। फिर भी ये रणनीतिक बदलाव व्यापक गिरावट को रोकने में नाकाम रहे हैं। 'द डेली स्टार' अख़बार के कंसल्टिंग एडिटर कमाल अहमद कहते हैं कि यह द्विपक्षीय रिश्तों का सबसे निम्नतम स्तर है।' बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद युनूस के प्रेस सचिव शफ़ीक़ुल आलम भारत के साथ संबंधों को 'बहुआयामी' बताते हैं, जो राजनीति जितना ही भूगोल पर भी टिके हैं। अगर बांग्लादेशियों से पूछा जाए कि वे 15 साल से ज़्यादा समय तक आज़ादी से वोट क्यों नहीं कर पाए, तो कई लोग एक ही जवाब देते हैं, शेख़ हसीना की तानाशाही और भारत का उनको 'समर्थन।' इस बीच, भारत का कहना है कि स्वतंत्र स्रोतों ने अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ 2900 से ज़्यादा हिंसक घटनाओं का दस्तावेज़ीकरण किया है, जिनमें हत्याएं, आगज़नी और ज़मीन पर क़ब्ज़ा शामिल है। भारत की तरफ़ से बांग्लादेश के 'बिगड़ते सुरक्षा माहौल' पर चिंता जताई गई है और 'मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी और भरोसेमंद चुनाव' शांतिपूर्ण तरीक़े से कराने की मांग की गई है। राजनीतिक तनाव अब आर्थिक रिश्तों में भी झलकने लगा है। थिंक टैंक सेंटर फ़ॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) की फ़हमीदा खातून कहती हैं राजनीतिक तनाव ने आर्थिक तनाव को जन्म दिया है। हमारा टकराव भारत सरकार या उसके ढांचे से है। लोगों से नहीं।'

हालांकि चुनावी प्रचार में भारत-विरोधी तेवर काफ़ी दबे हुए दिखे हैं, इसलिए नहीं कि वे ख़त्म हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि हर राजनीतिक दावेदार जानता है कि भारत के साथ रिश्ते को टालना नामुमकिन है। फिर भी भारत-बांग्लादेश रिश्तों की मरम्मत न तो जल्द होगी और न ही ऊपरी तौर पर। रियाज आलम कहते हैं कि 'किन्हीं भी देशों के बीच का रिश्ता ऐसा नहीं होता। लेकिन सुधार की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर दिल्ली पर है और इसके लिए ढाका को पसंदीदा मध्यस्थों के इस्तेमाल की आदत से आगे बढ़ना होगा। राजनीतिक नेता इस रीसेट को रणनीति के साथ नैतिकता के सवाल के रूप में भी देखते हैं। सुधार की वह गुंजाइश अब भी मौजूद है और नई सरकार फ़र्क़ ला सकती है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

मंजरित आम्र-वन-छाया में
हम प्रिये, मिले थे प्रथम बार,
ऊपर हरीतिमा नभ गुंजित,
नीचे चन्द्रातप छना स्फार!
तुम मुग्धा थी, अति भाव-प्रवण,
उकसे थे, अँबियों-से उरोज,
चंचल, प्रगल्भ, हँसमुख, उदार,
मैं सलज,..तुम्हें था रहा खोज!
छनती थी ज्योत्स्ना शशि-मुख पर,
मैं करता था मुख-सुधा पान,..
कूकी थी कोकिल, हिले मुकुल,
भर गए गन्ध से मुग्ध प्राण!
तुमने अधरों पर धरे अधर,
मैंने कोमल वपु-भरा गोद,
था आत्म-समर्पण सरल, मधुर,
मिल गए सहज मारुतामोद!
मंजरित आम्र-द्रुम के नीचे
हम प्रिये, मिले थे प्रथम बार,
मधु के कर में था प्रणय-बाण,
पिक के उर में पावक-पुकार!

- सुमित्रानंदन पंत

अफसरों का भी तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड!

● फाइलें लटकाईं तो मिलेंगे माइनस मार्क्स, बन गया प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार ने हाल ही में सिविल सेवकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने यूनियन सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के लिए एक विस्तृत स्कोर कार्ड सिस्टम लागू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब अधिकारियों का मूल्यांकन केवल आकलन से नहीं, बल्कि तय मानकों के आधार पर अंकों के जरिए किया जाएगा।

कैबिनेट सचिवालय की ओर से शुरू की गई इस प्रणाली में मेरिट और लापरवाही दोनों को स्पष्ट मापदंडों पर परखा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों को 100 अंकों के पैमाने पर आंका जाएगा। इसमें दर्जनों पैरामीटर शामिल हैं। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड में नेगेटिव मार्किंग और डिस्क्रेशनरी मार्क्स की भी व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर सरकारी कामकाज में देरी खत्म करने पर जोर दे चुके हैं। इसी दिशा में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का कहना है कि उचित मूल्यांकन से नागरिकों, बिजनेस और स्टार्टअप को इजाजत, ग्रांट और लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं में तेजी मिलेगी। कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 के लिए तैयार पहला प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2026 में सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को भेज दिया है।

फाइल निपटान को सबसे ज्यादा 20 अंक दिए जाएंगे

मूल्यांकन के मानकों में फाइल निपटान को सबसे ज्यादा 20 अंक दिए गए हैं। इसके बाद आउटपुट और गतिविधियों को 15 अंक तथा योजनाओं और कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर खर्च को भी 15 अंक का वेटेज दिया गया है। अन्य मानकों में जन शिकायत निवारण, कैबिनेट नोट की तैयारी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की समय पर पूर्ति, और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस तथा चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स द्वारा बिलों की समय पर मंजूरी शामिल हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में 12 नेगेटिव अंक का प्रावधान है। ये अंक विदेशी दौरों या आयोजनों पर अत्यधिक खर्च, सचिव स्तर पर फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को भुगतान में देरी जैसी स्थितियों में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा 5 डिस्क्रेशनरी अंक का भी प्रावधान रखा गया है, जिन्हें कैबिनेट सचिव किसी सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट के असाधारण कार्य या विशेष योगदान के लिए दे सकते हैं।

कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी, सपने न देखें

● बाराबंकी में सीएम योगी की दो टूक, दिया बयान

बाराबंकी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश से बाबरी मस्जिद विवाद का जिन्न एक बार फिर फूट पड़ा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश चल रही है।

वहीं, विवाद की लौ अब यूपी तक भड़कती दिखने लगी है। मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। यूपी में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एक बार फिर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हवा देने की कोशिश चल रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है।

इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मुद्दे पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं होगा, कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनेगा। मंगलवार को बाराबंकी के श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित दशम श्री हनुमान विराट महायज्ञ एवं श्री रामार्चा पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह सरकार जो बोलती है, करके दिखाती है। यह जितना करती है, उतना ही बोलती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे...। सीएम योगी ने सवालिया लहजे में जनसमूह से पूछा कि क्या आज कोई संदेह है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचा नहीं बनेगा।

पूर्व के हालातों की चर्चा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिकैतनगर के दुल्हदेपुर कुटी में आयोजित दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्रीरामार्चा पूजन में शामिल होकर पूजा-अर्चना की। सीएम योगी यज्ञ मंडप में आहुति देते दिखे। कार्यक्रम में पहुंचने पर संत बलराम दास ने उन्हें मखाने और लावा की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने वर्ष 2017 से पहले यूपी के हालात की चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में हालात ऐसे थे कि हर चौथे दिन शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ता था। कोई भी पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे। अब प्रदेश में अराजकता समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में विकास की नई गति दिखाई दे रही है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए कई फैसले

तलाकशुदा पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन की पात्रता

2585 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा गेहूं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की निरंतरता के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार जनजातीय कार्य विभाग की पीवीटीजी आहार अनुदान योजना के लिए 2,350 करोड़ रूपये, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 1,703 करोड़ 15 लाख रूपये, सीएम राइज विद्यालय योजना के लिए 1,416 करोड़ 91 लाख रूपये, आवास सहायता योजना के लिए 1,110 करोड़ रूपये के साथ ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति, कक्षा-9वीं की छात्रवृत्ति के लिए 522 करोड़ 8 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अभी तक पुत्रों को ही पेंशन प्राप्त होती थी अब तलाकशुदा पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। मोहन कैबिनेट में पेंशन योजना में बदलाव के अंतर्गत या व्यवस्था लागू की है। अभी तक सिर्फ पुत्रों को ही पारिवारिक पेंशन मिलती थी। कंप्यूटर ऑपरेटर को 5 वर्ष की छूट देने का पैसा हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर लिया गया है।

आबकारी नीति को मंजूरी

बैठक में आबकारी नीति 2026-27 को भी मंजूरी दी जा सकती है। सरकार शराब से राजस्व बढ़ाने के फैसले पर निर्णय ले सकती है। साथ ही सोयाबीन की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य तय कर किसानों से खरीदी करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में आ सकता है। बैठक से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन 7 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 7 मार्च तक चलेगा। इसके लिए प्रदेशभर में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए अधिक रखा गया है। अनुमोदन अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरण कंपनी स्तर पर निर्धारित सीलिंग कॉस्ट का पालन करते हुए, 2 लाख रुपये प्रति घर तक अनुमानित लागत वाली बसाहटों में राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधोसंरचना निर्माण कर ऑन-लाइन प्रणाली से विद्युतीकरण किया जायेगा। खेतों पर बने घरों के साथ ही 5 घरों से छोटी बसाहटें एवं ऐसी दूरस्थ बसाहटें, जहाँ विद्युतीकरण की औसत लागत रूपये 2 लाख प्रति घर से अधिक है, उनमें म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा 1 किलोवाट क्षमता के ऑफ-ग्रिड प्रणाली (सोलर + बैटरी) से विद्युतीकरण किया जायेगा।

शबाना महमूद बन सकती हैं ब्रिटेन की पहली मुस्लिम पीएम

● कश्मीर मूल की हैं, एपस्टीन फाइल्स विवाद से पीएम स्टार्मर की कुर्सी खतरे में

लंदन (एजेंसी)। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े विवादों के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में है। अब उनकी अपनी लेबर पार्टी के एक धड़े ने ही इस्तीफे की मांग कर दी है। हालांकि स्टार्मर अभी पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच, नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग और पूर्व उपप्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है। शबाना महमूद कश्मीर के पीओके के मीरपुर मूल की हैं। वह ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी।

हिमंता शूटिंग वीडियो विवाद, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

● सीजेआई बोले-चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित वीडियो को लेकर सीपीएम के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वीडियो में मुख्यमंत्री एक मुस्लिम लोगों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीनियर वकील निजाम पाशा ने मंगलवार को यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के भाषणों और हाल में सामने आए वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। निजाम पाशा ने यह भी बताया कि इस मामले में संबंधित

अधिकारियों को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा।

● **कांग्रेस ने पहले उठाया था वीडियो का मुद्दा-** दरअसल, 8 जनवरी को कांग्रेस ने दावा किया कि असम बीजेपी एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा मुसलमानों को गोली मारते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये वीडियो अल्पसंख्यकों की टार्गेटेड पॉइंट-ब्लैंक हत्या को बढ़ावा देने जैसा है। कांग्रेस का दावा है कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स हैंडल पर दिख रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कथित तौर पर एक राइफल से निशाना साधते और दो लोगों पर गोली चलाते हुए दिख रहे थे। निशाने में दिख रही तस्वीर में एक ने टोपी पहनी थी और दूसरे की दाढ़ी थी। इसका कैप्शन पॉइंट-ब्लैंक शॉट था। श्रीनेत के शेयर किए गए वीडियो में असम की भारतीय जनता पार्टी का एक्स अकाउंट नजर आ रहा है।

● **कांग्रेस महासचिव बोले- यह नरसंहार का आह्वान-** वीडियो वायरल होने के बाद संगठन के प्रभारी कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की। वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा- एक आधिकारिक बीजेपी हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अल्पसंख्यकों की टारगेटेड, पॉइंट-ब्लैंक हत्या दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि यह नरसंहार का आह्वान करने के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसा सपना जिसे यह फासीवादी शासन दशकों से पाले हुए है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 11 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया-वांगचुक बिल्कुल ठीक

● एम्स में अच्छा इलाज मिल रहा, हिरासत पर विचार की है मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक बिल्कुल ठीक हालत में हैं। हिरासत में रहते हुए उन्हें एम्स जोधपुर में अच्छा इलाज मिल रहा है। वांगचुक के वकील ने कहा कि उनकी हिरासत पर फिर से विचार करने का यह सही समय है क्योंकि वह अभी भी अस्वस्थ हैं। केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि वांगचुक की हिरासत पर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच वांगचुक की

गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। 11 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल, 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया गया था। तब से वे जोधपुर जेल में हैं। इससे पहले 2 फरवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को और जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि वांगचुक के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सीधा खतरा दिखता है।

बांग्लादेश चुनाव से पहले फिर हुई हिंसा

● दुकान में घुसकर हिंदू कारोबारी की बेरहमी से हत्या

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। सोमवार देर रात मैमनसिंह जिले में एक हिंदू व्यापारी की उसकी दुकान के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि मरने वाले की पहचान 62 साल के सुशेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है। वह साउथकांडा के रहने वाले थे। सुशेन चावल व्यापारी थे और त्रिशाल उपजिला के बोगर बाजार में उनकी

'मेसर्स भाई भाई एंटरप्राइज' नाम से एक दुकान थी। इस हत्या के बाद भारत में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बांग्लादेश को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। मैमनसिंह जिला पुलिस ने बताया है कि यह घटना रात करीब 11 बजे हुई। सुशेन चंद्र सरकार अपनी दुकान के अंदर मौजूद थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने हत्या करने के बाद दुकान का शटर गिरा दिया और शव को अंदर छोड़कर मौके से फरार हो गए।

बच्चों के गायब होने को लेकर 'सुप्रीम' सख्ती

● कहा-देश भर में कोई नेटवर्क तो नहीं, पता लगाए सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। बच्चों के लापता होने की खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पता करे कि इसके पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क तो नहीं है। अदालत ने कहा कि आप देखें कि क्या पूरे देश में ऐसा कोई नेटवर्क है या फिर किसी राज्य में ही स्टेट लेवल पर ऐसा चल रहा है। बीते कुछ दिनों में बच्चों के गायब होने की खबरें काफी ज्यादा देखी गई थीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कोई एक ही पैटर्न है या फिर ऐसी घटनाओं में आपस में कोई संबंध नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह ऐसी घटनाओं का सभी राज्यों से ब्योरा

जुटाए। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों की ओर बच्चों के लापता होने का डेटा दिया गया है। ऐसे मामलों में चल रहे मुकदमों का स्टेटस भी मिला है, लेकिन अब भी करीब एक दर्जन ऐसे राज्य हैं, जहां से जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐश्वर्या ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरा डेटा मिलने के बाद ही उसका विश्लेषण किया जा सकता है। इस पर बेंच ने भाटी से कहा, %हम यह जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कोई राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है या फिर राज्य स्तर पर ही ऐसा कुछ हो रहा है। यह कोई पैटर्न है या फिर इन घटनाओं में कोई आपसी ताल्लुक नहीं है।

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश

● 118 सांसदों के दस्तखत,2 बार स्थगन के बाद लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बजट सत्र के 10वें दिन मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में कार्यवाही नहीं हो सकी। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महज 1 मिनट बाद चेयर पर मौजूद पीसी मोहन 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बीच भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसद वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दें।

नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन पर एफआईआर

● राहुल इसकी कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे

● दावा किया-चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के सर्कुलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर सामने आई जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही है। पुलिस के मुताबिक, इस

किताब के पब्लिकेशन के लिए अभी संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी टाइटल वाली एक टाइप-सेट किताब की कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी। आशंका जताई गई है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो कॉपी तैयार की थी, यह वही हो सकती है। इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब के कवर को इस तरह दिखाया गया, जैसे वह खरीद के लिए उपलब्ध हो। इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाली किताब की सामग्री कैसे सार्वजनिक हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। यह एफआईआर ऐसे समय दर्ज की गई है, जब 4 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद परिसर में किताब की एक कॉपी दिखाते हुए देखा गया था। राहुल ने कहा था- अगर पीएम मोदी संसद आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। लोकसभा में 2-3 फरवरी को राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की थी।

असम के हाईवे पर उतर सकता है मोदी का प्लेन

● यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली इमरजेंसी एयरस्ट्रिप होगी

● प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता

है तो यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा। यह एयरस्ट्रिप नेशनल हाईवे (एनएच) 127 के डिब्रूगढ़-मोरान हिस्से पर बनाई गई है। पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेकऑफ दिखाएंगे। डेमो करीब 30-40 मिनट का होगा। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी फाइटर एयरक्राफ्ट में मोरन हाईवे पर उतरेंगे। मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री 4.4 किमी के एयरस्ट्रिप के उद्घाटन के लिए मोरन आएंगे। यह कार्यक्रम भारत की आपदा तैयारी, पूर्वोत्तर विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाएगा। पीएम की यात्रा सिविल-मिलिट्री दोहरे उपयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमो एयरस्ट्रिप की क्षमता पर फोकस करेगी।

डबरा में कलश बांटते वक्त भगदड़, महिला की मौत

● बच्ची समेत 8 घायल, महिलाओं को कुचलते निकली भीड़

डबरा (नप्र)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई। इसमें 70 वर्षीय महिला रति साहू की मौत हो गई। बच्ची समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है। ग्वालियर रेफर किया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। महिलाएं एक दूसरे पर गिर गईं। वहीं मृतक महिला की बहू ने बताया कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हादसा हुआ। भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया। इसी वजह से सास रति साहू को भीड़ कुचलते निकल गई। घायल सास को अस्पताल लेकर गए, तो डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती। यहां ऑक्सीजन के लिए मेरी सास 30 मिनट तक तड़पती रही।

दोपहर में थी यात्रा, लेकिन सुबह से जुट गई थी भीड़- नवग्रह शक्तिपीठ प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत दोपहर 1 बजे कलश यात्रा प्रस्तावित थी। इसके लिए महिलाओं को सुबह 11 बजे स्टेडियम पहुंचने को कहा गया था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही महिलाएं बड़ी संख्या में ग्राउंड पर जुटने लगी थीं। भीड़ लगातार बढ़ती रही, लेकिन एंट्री गेट और अंदरूनी व्यवस्था के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया गया। दावा है कि कलश यात्रा के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन भगदड़ के वक्त लोगों को 2 पुलिसकर्मी ही बचते दिख रहे हैं। हादसे के बाद स्टेडियम ग्राउंड में हर तरफ महिलाओं की चप्पलें, टूटी चूड़ियां और बिखरा सामान पड़ा मिला। यह दृश्य भगदड़ की भयावहता को बयान कर रहा था। कई महिलाएं हादसे के बाद भी ग्राउंड पर बैठी नजर आईं। उनका कहना था कि उन्हें यात्रा के लिए बुलाया गया था, लेकिन न तो कलश मिला और न ही सही जानकारी दी गई।

बढ़ते अपराधों को लेकर घिर गए बिहार के सीएम

● तेजस्वी यादव का हमला,मुख्यमंत्री की भाषा पर जताया ऐतराज

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों ने भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने सदन से वाकआउट किया। बाद में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला किया। उन्होंने सरकार पर राज्य में बढ़ते अपराधों पर जवाब न देने और मुख्यमंत्री पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि, बिहार में अपराध में वृद्धि हो रही है। छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। नीट (छात्रा की मौत) का मामला ठंडा भी नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया। आरजेडी ने इस सवाल को सदन में उठाया। इसका जवाब देने के बजाय जिस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की इससे लोगों का मन और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि,क्राइम में वृद्धि हो रही है और छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। कई बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं।

● **विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन-** बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य अपराधों के बढ़ने पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायकों ने भारी हंगामा किया और उनको बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर वे वॉकआउट कर गए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वे आरोप लगा रहे थे कि बिहार में कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक विधानसभा के गेट पर नारे लगाते हुए देखे गए।

वर्ष-2027 तक देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने समन्वित प्रयास करें: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा

एमडीए-2026 अभियान का किया वर्चुअल शुभारंभ

भोपाल । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने 12 राज्यों के 124 जिलों के लिए 'मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान 2026' का नई दिल्ली से वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों और जिला परिषद सदस्य सहित सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि दवा का सेवन केवल वितरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दवा पूरी मात्रा में ली जाए।

केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि भारत सरकार 2027 तक लसीका फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे अभियान के दौरान सभी आवश्यक संसाधनों और जागरूकता गतिविधियों को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की भागीदारी और दवा का समय पर सेवन ही इस गंभीर रोग को समाप्त करने की कुंजी है।

नागरिक स्वयं दवा का सेवन करें, परिवार जन और पड़ोसियों को भी करें जागरूक: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस अभियान को 8 जिलों - छतरपुर, पन्ना, उमरिया, मऊगंज, टीकमगढ़, निवाड़ी, शहडोल और भिंड के 12 ब्लॉकों में संचालित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अपील की है कि वे नागरिक स्वयं दवा का सेवन करें, अपने परिवार जन और पड़ोसियों को जागरूक करें और स्वयंसेवक के रूप में अभियान में सक्रिय सहयोग दें।

रूस 'दोस्त' फिर भी भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव

● आधी से ज्यादा शिकायतें पुतिन के देश से, परिजन नाराज

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश में भारतीय छात्रों द्वारा की गई शिकायतों में से 50 प्रतिशत रूस से संबंधित हैं। विदेश मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय छात्रों द्वारा विश्व स्तर पर दर्ज की गई शोषण और नस्लीय भेदभाव की सभी शिकायतों में से 50 फीसदी से अधिक शिकायतें रूस से आती हैं, जिसमें मॉस्को सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।

आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 196 देशों में भारतीय छात्रों ने शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव की लगभग 350 शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें से 200 से अधिक शिकायतें अकेले रूस से आईं। दूसरे नंबर पर फ्रांस का स्थान रहा जहां 97 शिकायतें दर्ज की गईं। रूस में पढ़ रहे अधिकांश भारतीय मेडिकल छात्र राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु राज्यों से

आते हैं। अपेक्षाकृत कम ट्यूशन फीस और आसान प्रवेश प्रक्रियाओं के कारण रूस भारतीय छात्रों, विशेष रूप से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक बना हुआ है। हालांकि, भेदभाव की बढ़ती शिकायतों ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पिछले तीन सालों में ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। 2023 में 68 शिकायतें थीं जो 2024 में 78 हो गईं और फिर 2025 में बढ़कर 201 हो गईं। रिपोर्ट के अनुसार, रूस में रह रहे भारतीय छात्रों ने बताया कि उनके साथ अक्सर दूसरे देशों के छात्रों द्वारा भेदभाव किया जाता है। कुछ छात्रों ने तो विश्वविद्यालयों द्वारा मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है, जिसमें मामूली मुद्दों या उल्लंघनों पर निष्कासन की धमकियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से प्रतिशोध के डर या वीजा और इमिग्रेशन संबंधी जटिलताओं के कारण उनकी कई शिकायतें आधिकारिक माध्यमों तक नहीं पहुंच पातीं।

भारतीय छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव

विदेशी मेडिकल स्नातक संघों के सदस्यों ने भी रूस में भारतीय छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव, दुर्व्यवहार और संस्थागत समर्थन की कमी को स्वीकार किया। शिकायतों को शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है। छात्र चुपचाप पीड़ा सहते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय अक्सर उन्हें दरकिनार कर देते हैं। दावों के मुताबिक, रूसी नियमों के अनुसार प्रत्येक संस्थान में विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 200 तक सीमित है लेकिन कुछ विश्वविद्यालय 1200 से अधिक छात्रों को प्रवेश देते हैं और बाद में उन्हें निष्कासित कर देते हैं। इन मुद्दों के कारण हाल के वर्षों में रूस को चुनने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कम से कम 50त्न की गिरावट आई है। इसके अलावा, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और शैक्षणिक अनिश्चितता के कारण भारतीय छात्रों की रूस में एमबीबीएस करने में रुचि कम हो गई है। इस बीच, विदेश में शोषण और नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे भारतीय श्रमिकों और छात्रों के बारे में हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि शिक्षा और छात्र कल्याण से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों और दूतावासों में अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा, हमारे दूतावास विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं और उन्हें वहां रहने के दौरान आने वाली चुनौतियों और खतरों के बारे में जानकारी देते हैं। दूतावास प्रमुख और वरिष्ठ दूतावास अधिकारी अपने-अपने मान्यता प्राप्त देशों में स्थित विदेशी शिक्षण संस्थानों का दौरा करते हैं ताकि भारतीय छात्रों से बातचीत कर सकें।

लव जिहाद में इस्तेमाल 3 कारें जब्त

- **आरोपी बोला- छात्रा के वीडियो दो दोस्तों को भेजे; फोन तोड़कर अजमेर में फेंका था**

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 11वीं की छात्रा से रेप, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग सहित अश्लील वीडियो वायरल करने के सह आरोपी माज खान से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार रात उसकी निशानदेही पर तीन कारें- मारूति सियाज, स्विफ्ट और होंडा सिटी जब्त कर ली गईं।

इन सभी कारों में अलग-अलग जगहों पर माज के साथी ओसाफ अली खान ने छात्रा के साथ रेप किया था। थार की तलाश में कोहेफिजा थाने की एक टीम रवाना हुई है। इसे जल्द जब्त करने का दावा किया जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि माज अपने मोबाइल को लेकर लगातार गुमराह कर रहा है। उसका कहना है कि वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए अजमेर गया था। वहां जैसे ही लव जिहाद केस में अपना नाम आने की जानकारी मिली, उसने मोबाइल फोन तोड़कर जंगल में फेंक दिया। हालांकि, पूछताछ में उसने छात्रा की वीडियो अन्य दो दोस्तों के साथ शेयर करने की बात मानी है। पुलिस अब उन्हें भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब करेगी। आरोपियों ने अन्य छात्राओं को तो निशाना नहीं बनाया, इसकी तहकीकात की जाएगी। बता दें कि रविवार को कोहेफिजा थाना पुलिस ने माज को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 13 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

खानूगांव में कार के अंदर छात्रा से किया था रेप- दरअसल, 2 जनवरी को कोहेफिजा पुलिस ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता ने खानूगांव इलाके में कार में रेप करने, धर्म बदलने का दबाव बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 जनवरी को ओसाफ अली खान (19) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 8 फरवरी को दूसरे आरोपी माज खान की गिरफ्तारी की गई। वारदात में इस्तेमाल काले कांच की थार, माज की ही थी। पूरा घटनाक्रम उसकी जानकारी में था।

माज का बड़ा भाई एमडी तस्करी केस में जमानत पर है- माज का बड़ा भाई मोनिस मादक पदार्थों की तस्करी मामले में जमानत पर है। मोनिस का एमडी तस्करी, लव जिहाद और जमीनें कब्जा करने वाले यासीन मछली गैंग से रिश्ता भी सामने आ चुका है। वहीं, माज खुद को एक प्रतिष्ठित जिम का संचालक बताता है। पुलिस उसके फोन की सीडीआर डिटेल खंगाल रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट का भी परीक्षण कराया जा रहा है।

पुलिस बोली- थार के बारे में जानकारी नहीं दे रहा माज- कोहेफिजा थाने के प्रभारी कृष्ण गोपाल शुक्ला ने कहा- माज खान लगातार गुमराह कर रहा है। उसने बताया कि मोबाइल को तोड़कर अजमेर में फेंका है। थार के संबंध में भी जानकारी नहीं दे रहा है। दो अन्य संदेहियों के नाम उसने बताए हैं। हम उनसे पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं।

मानव अधिकार आयोग (कार्यवाहक) अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों एवं ऑक्सीजन प्लांट और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया।

भोपाल स्टेशन एफओबी हादसा

मरने के बाद मिला इंसाफ

रेलवे का तर्क- यात्रा खत्म, जिम्मेदारी खत्म; आयोग ने कहा- स्लैब गिरना गंभीर लापरवाही

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज हादसे में रेलवे जिस दलील के सहारे जिम्मेदारी से बचना चाहता था, उसे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने सख्ती से खारिज कर दिया है। रेलवे का तर्क था कि ट्रेन से उतरते ही यात्री की यात्रा समाप्त हो जाती है और स्टेशन की सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि फुटओवर ब्रिज रेल यात्रियों के लिए अनिवार्य सुविधा है और उसका स्लैब गिरना सीधे तौर पर रेलवे की लापरवाही तथा सेवा में कमी का प्रमाण है।

आयोग ने माना कि यात्रियों के उपयोग में आने वाले फुटओवर ब्रिज का न तो सही ढंग से निर्माण किया गया था और न ही समय-समय पर उसका रखरखाव किया गया। यही लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बनी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल परिवादी खालिद बेग की मृत्यु 19 नवंबर 2023 को हो चुकी है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल ने यह फैसला सुनाया।

रेलवे का तर्क: फुटओवर ब्रिज हमारी जिम्मेदारी नहीं- रेलवे की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन में कहा है कि परिवाद में दर्ज पीएनआर से संबंधित टिकट, एफआईआर और मेडिकल दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिन पर पृथक से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 2(14) का हवाला देते हुए कहा कि किराया

केवल यात्री को ट्रेन में यात्रा कराने के लिए लिया जाता है। रेलवे के अनुसार, जैसे ही यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर उतरता है, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। इसके बाद स्टेशन पर उपलब्ध सभी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं।

इसी आधार पर रेलवे ने परिवाद को प्रचलन योग्य नहीं मानते हुए उसे खारिज करने की मांग की। रेलवे ने अपने पक्ष में पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक आर.के. पाराशर का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया।

आयोग की टिप्पणी- जिम्मेदारी से नहीं बच सकता रेलवे- आयोग ने रेलवे के पूरे तर्क को अस्वीकार कर दिया। आदेश में कहा गया कि परिवादी रेलवे द्वारा संचालित ट्रेन से यात्रा कर रहा था और रेलवे द्वारा निर्मित फुटओवर ब्रिज से स्टेशन के बाहर निकल रहा था, तभी ब्रिज का स्लैब गिर गया।

आयोग ने स्पष्ट किया कि फुटओवर ब्रिज का उपयोग यात्रियों द्वारा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तथा स्टेशन से बाहर निकलने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। ऐसे में इसका सुरक्षित निर्माण और समय-समय पर रखरखाव सुनिश्चित करना रेलवे का दायित्व है।

यह थी घटना

13 फरवरी 2020 को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज से यात्रियों के गुजरने के दौरान अचानक लगभग 10x10 वर्गफुट का कांक्रीट स्लैब भरभराकर नीचे गिर गया। हादसे में 10 से 15 यात्री मलबे में दब गए। यात्रियों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों में यात्री खालिद बेग भी शामिल थे। वे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से काचीगुड़ा (हैदराबाद) से भोपाल पहुंचे थे और ट्रेन से उतरने के बाद परिजनों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर-2 से बाहर निकल रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब गुरुवार सुबह करीब 9:03 बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर आकर रुकी थी। यात्री उतर ही रहे थे कि अचानक जोरदार आवाज के साथ फुटओवर ब्रिज का रैंप टूटकर गिर गया। चीख-पुकार मच गई। कई यात्री मलबे में दब गए, कई लहूलुहान हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक, हादसे के वक्त भी ब्रिज पर यात्रियों की भीड़ थी। आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ ने तुरंत राहत-बचाव शुरू किया।

एक ही परिवार के सात लोग घायल- इस ट्रेन से हैदराबाद से एक ही परिवार के 34 लोग शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में इसी परिवार के 7 लोग घायल हो गए। सभी पुराने शहर के निवासी बताए गए। घायलों में मंगलवारा छावनी निवासी खालिद बेग भी शामिल थे, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी।

अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

आंतरिक सुरक्षा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग श्री शिव शेखर शुक्ला की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तथा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करना रहा। इस दौरान आपराधिक न्याय प्रणाली, फॉरेंसिक व्यवस्था, जेल प्रबंधन, साइबर अपराध नियंत्रण, आतंकवाद निरोध, मादक पदार्थ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण सहित राज्य से जुड़े अन्य विशिष्ट मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा) सुश्री निष्ठा तिवारी एवं संयुक्त निदेशक सुश्री अमृता डेस, उपस्थित रहीं। अतिथियों का औपचारिक स्वागत पुलिस महानिरीक्षक एवं सचिव, गृह विभाग श्रीमती कृष्णावेणी देशावतु द्वारा किया गया। समीक्षा बैठक में गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक अभियोजन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने सहभागिता की।

बैंक कर्मचारी ने गोली मारकर खुदकुशी की

इंदौर में घर खाली कराने पहुंची थी टीम; मकान पर ढाई करोड़ का कर्ज था

इंदौर (नप्र)। इंदौर में बैंककर्मी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना विजय नगर में सिनर्जी अस्पताल के पास सोमवार शाम करीब साढ़े 5 बजे की है। मृतक का नाम हेमंत पिता एसडी ब्रह्मवंशी बताया गया है। वह को-ऑपरेटिव बैंक में काम करता था।

हेमंत ने अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ढाई करोड़ का कर्ज ले रखा था। डेढ़ साल से किश्त न चुकाने पर बैंक की टीम मकान खाली कराने पहुंची थी। बैंक के कर्मचारी मकान की पहली मंजिल पर लिखा-पढ़ी कर रहे थे, इसी दौरान हेमंत ने आत्महत्या कर ली। हेमंत के परिवार में दो लड़के, एक लड़की और मां हैं। हेमंत का बड़ा बेटा एक आईटी कंपनी में कार्यरत है। उनका दूसरा बेटा वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है। बेटी पुणे में अध्ययनरत है। हेमंत अकाउंट सेक्शन में पदस्थ था।

मप्र में 12वीं के करीब 7 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू गई हैं। सोमवार को पहले दिन अंग्रेजी का पेपर संपन्न हुआ। इस साल करीब 7 लाख स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं के फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, सीसीटीवी निगरानी और थानों से प्रश्न-पत्र निकालने तक वीडियोग्राफी की गई है। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक होंगी। भोपाल के 104 सेंटर पर 2600 के करीब स्टूडेंट ने मंगलवार को एग्जाम दिया है।

प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल- इस बार प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 9 लाख 7 हजार विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा देंगे, जबकि करीब 7 लाख छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं।

इतने बड़े स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकलमुक्त और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं।

परीक्षार्थी बोले- पेपर आसान रहा- सोमवार को हुए 12वीं अंग्रेजी के पर्चे के बाद सेंटर से निकलते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि पेपर ठीक और मिलाजुला रहा है। जलज शर्मा ने बताया कि आज का एग्जाम

3856 केंद्रों पर पहला पेपर, भोपाल में 2600 छात्रों ने दी परीक्षा

बहुत अच्छा रहा। उन्नति ने बताया कि एग्जाम जैसा सोचा था वैसा ही आया। वंश ठाकुर ने बताया कि पेपर आसान था। जैसा सोचा वैसा ही आया था।

3856 परीक्षा केंद्र, हर जिले में सख्त निगरानी- बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। भोपाल की बात करें तो यहां 10वीं के 30 हजार 746 और 12वीं के 26 हजार 627 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इन छात्रों के लिए भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में चार-चार फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए हैं।

इनमें से दो स्क्वॉड विकासखंड स्तर पर और दो जिला स्तर पर काम करेंगे। हर स्क्वॉड में तीन सदस्य होंगे और तीनों पुलिस या प्रशासनिक स्तर के अधिकारी होंगे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

संवेदनशील केंद्रों पर 'तीसरी आंख' का पहरा- नकल और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए इस बार तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

इन केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर भोपाल स्थित बोर्ड कार्यालय से सीधी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, थानों से प्रश्न-पत्र निकालने के दौरान भी वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है और सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की गई है। इसका मकसद है कि परीक्षा प्रक्रिया की हर कड़ी पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।

प्रदेश की बिजली कंपनियों पर 49 हजार करोड़ कर्ज

प्रदेश के तीन डिस्कॉम 71 हजार करोड़ के घाटे में, मप्र 'अस्थिर' राज्यों की लिस्ट में पहुंचा

भोपाल (नप्र)। देश की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने भले ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली बार मुनाफा कमाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां अब भी भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। केंद्र सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश की डिस्कॉम पर 31 मार्च 2025 तक 49,239 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि राज्य में 71,394 करोड़ रुपए का संचयी घाटा दर्ज किया गया है। यह जानकारी बिजली राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एमपी की देनदारी 'अस्थिर' राज्यों में शामिल

केंद्र सरकार ने बताया कि जिन छह राज्यों की डिस्कॉम देनदारी को नियामक द्वारा 'अस्थिर' माना गया है, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। छह राज्यों (उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु) पर देश के कुल डिस्कॉम कर्ज का 66 प्रतिशत हिस्सा है। इन राज्यों की कुल अस्थिर देनदारी करीब 2.74 ट्रिलियन रुप, बताई गई है।

तीनों वितरण कंपनियों पर भारी बोझ

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

देश स्तर पर मुनाफा, एमपी में सुधार

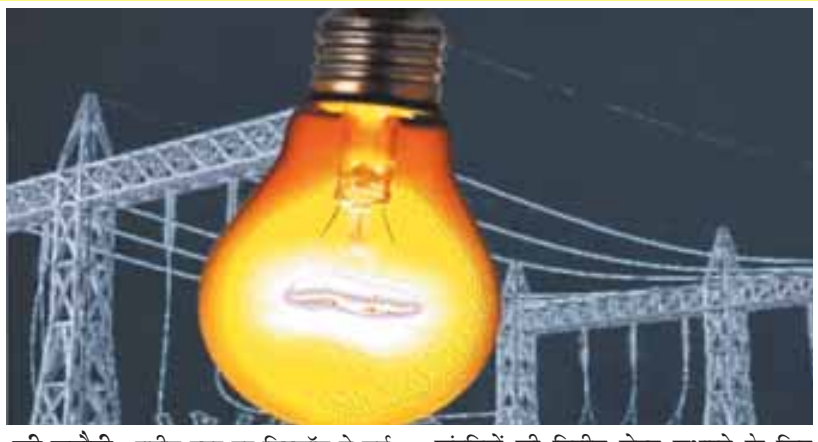

की चुनौती- राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कॉम ने वर्ष 2025 में 2,701 करोड़ रुपए का कर पश्चात मुनाफा दर्ज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पुराने घाटे और कर्ज की भरपाई अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सुधार योजनाओं से उम्मीद- केंद्र सरकार ने बताया कि डिस्कॉम की वित्तीय हालत सुधारने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) लागू की गई है, जिसमें फंडिंग को राज्यों के प्रदर्शन से जोड़ा गया है। साथ ही राज्यों को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधारी की अनुमति भी दी गई है, बशर्ते बिजली क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार किए जाएं। सरकार का कहना है कि तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

संचयी घाटा क्या होता है?

संचयी घाटा का मतलब है बिजली कंपनियों को हर साल जो नुकसान होता गया, वह जुड़ता चला गया और सालों बाद एक बड़ी रकम बन गया। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी को एक साल 5 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। अगले साल 7 हजार करोड़ का और फिर 10 हजार करोड़ का तो यह सभी नुकसान मिलकर जो कुल रकम बनती है, वही संचयी घाटा कहलाती है।

सबसे ज्यादा हानि (संचयी घाटा) वाले राज्य

तमिलनाडु - 1,19,153 करोड़
उत्तर प्रदेश - 1,00,858 करोड़
राजस्थान - 90,303 करोड़
मध्य प्रदेश - 71,394 करोड़
महाराष्ट्र - 35,671 करोड़

डिस्कॉम पर सबसे ज्यादा कर्ज वाले टॉप-5 राज्य

राजस्थान - 98,488 करोड़
महाराष्ट्र - 90,659 करोड़
आंध्र प्रदेश - 77,583 करोड़
उत्तर प्रदेश - 61,395 करोड़
तमिलनाडु - 1,01,782 करोड़

छतरपुर में करंट लगते ही 25 फीट नीचे गिरा लाइनमैन

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर के अमरपुरा गांव में मंगलवार को बिजली का खंभा सुधारते समय एक आउटसोर्स कर्मी हादसे का शिकार हो गया। करंट लगने से वह करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

लाइन सुधारने चढ़ा था खंभे पर- घटना सटई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। बताया गया कि 29 वर्षीय दयाशंकर पटेल बिजली लाइन ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े थे। इसी दौरान अचानक करंट लग गया। करंट लगने से दयाशंकर अपना संतुलन खो बैठे और सीधे जमीन पर आ गिरे। गिरने की ऊंचाई ज्यादा होने से उन्हें गंभीर चोटें आईं।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. शुक्ल की जयंती पर किया नमन

मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में की पुष्पांजलि अर्पित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. शुक्ल के परिजन ने भी चित्र पर पुष्पांजलि की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, वर्ष 1985 से 1990 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। लोकप्रिय जन नेता रहे श्री शुक्ल राज्य सरकार में विधि-विधायी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद, उन्होंने 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने असंसदीय अभिव्यक्तियां नामक पुस्तक की संकल्पना की, जो विधायी कामकाज पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। उन्होंने संसदीय मामलों सहित कई पुस्तक लिखीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे व्यक्तित्वों की जयंती और पुण्यतिथि पर मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में उन्हें स्मरण करने की परंपरा स्थापित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर की सराहना करते हुए उनका आभार माना।

संपादकीय

घुटनों पर पाक!

पाकिस्तान अपनी तमाम पैंतरेबाजी के बाद आखिर आईसीसी टी 20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ 15 फरवरी को अपना ग्रुप मैच खेलने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और पाक सरकार का असल मकसद इस मुद्दे पर भारत को नीचा दिखाना था, जिसे आईसीसी ने अपनी सधी हुई चालों से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने इसे यह कहकर मुद्दा बनाया था कि आईसीसी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर दोहरा मानदंड अपना रहा है। वह इस मुद्दे पर भारत का स्टैंड सही मानता है, लेकिन जब यही बात बांग्लादेश ने भारत में उसके खिलाड़ियों को खेलने को लेकर उठाई तो आईसीसी ने उसे बाहर होने पर विवश किया। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी जो पाक सरकार में मंत्री भी हैं, रोजाना नई नई बहानेबाजी करते रहे। आखिर में कहा गया कि जो पाक सरकार कहेगी, वही करेंगे। खुद पाकिस्तान में भी टी 20 वर्ल्ड कप ग्रुप मैच में पाक टीम के भारत के साथ न खेलने को लेकर अलग-अलग राय थी। दरअसल यह मैच समूचे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और कीमती मैच होना था, जिस पर बड़ी रकम भी दांव पर लगी थी। कहने को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका असल मकसद आईसीसी से ज्यादा पैसे ऐंठने का था। साथ ही वह यह भी चाहता था कि भारतीय टीम पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाए, भारत, पाक और बांग्लादेश की क्रिकेट सीरिज हो तथा भारत की तरह उसे भी आईसीसी की कमाई में ज्यादा हिस्सा मिले। आईसीसी की कमाई में भारत को 38 फीसदी तो पाक महज 6 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है। शुरू में आईसीसी ने पाक को समझाने की बहुतेरी कोशिशें कीं, मैच से हटने पर भारी आर्थिक नुकसान की चेतावनी भी थी, लेकिन पाक अपनी चालें चलता रहा। अंततः आईसीसी ने पाक को उसी के दावं चित किया। आईसीसी ने इस काम में श्रीलंका सरकार और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड तथा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पाक पर दबाव बनाने के काम पर लगाया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने श्रीलंका पाक रिश्तों की दुहाई देते हुए कहा कि भारत पाक ग्रुप मैच चूंकि कोलंबो में होना है, इसलिए उसके रद्द होने पर भारी नुकसान हमे ही होगा,जो दोनों देशों के सम्बन्धों की दृष्टि से अनुकूल नहीं होगा। उसी प्रकार बांग्लादेश ने भी पाक पर मैच खेलने के लिए दबाव डाला। उधर आईसीसी ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया कि टूर्नामेंट का बहिष्कार करने के बाद भी उसका न तो कोई आर्थिक नुकसान होने दिया जाएगा और न ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा। आईसीसी की यह चाल काम कर गई और पाकिस्तान, जिसके पास पहले ही कोई बहिष्कार का कोई ठोस तर्क नहीं था, लाइन पर आ गया। आईसीसी ने पीसीबी की कोई मांग या शर्त नहीं मानी। जब कोई चारा नहीं बचा तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 15 फ़रवरी को भारत के खिलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की अनुमति दे दी और कहा कि यह फ़ैसला मित्र देशों के अनुरोध पर लिया गया है। वैसे क्रिकेट का मुद्दा बांग्लादेश चुनाव में भी अहम हो गया है। इसके पूर्व बांग्लादेश ने पाकिस्तान का इस बात लिए आभार जताया था कि वह टूर्नामेंट बहिष्कार के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ है। लेकिन अब पाक के यू टर्न के बाद बांग्लादेश में क्या संदेश जाएगा, यह देखने की बात है। साफ है कि पाकिस्तान पर कोई आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। इस बार भी पाकिस्तान ने वही किया है। हालांकि इसके पीछे बड़ा डर आईसीसी के कठोर एक्शन और आर्थिक बदहली का भी था। आईसीसी ने दबाव में न आकर सही संदेश दिया है।

अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे लापता लोग

नजरिया

अमित बैजनाथ गर्ग

लेखक पत्रकार हैं।

हाल ही में दिल्ली में 807 लोगों के लापता होने की खबर छपी। इनमें 137 बच्चे और 63 फीसदी महिलाएं तथा लड़कियां शामिल हैं। यह कुल लापता लोगों का बड़ा हिस्सा है। बताया गया कि एक जनवरी से 27 जनवरी तक हर दिन औसतन 27 लोग गायब हुए। इन 807 मामलों में से केवल 235 लोगों का ही अभी तक पता लग सका है। वहीं 538 लोग अब भी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं लापता लोगों के परिवार भी पुलिस से सहयोग नहीं मिल पाने की शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली की इन घटनाओं ने एक बार फिर लापता लोगों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली से ही लोग लापता हुए हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में हर साल लापता लोगों के मामले सामने आते हैं।

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख लोग लापता होते हैं, जिनमें से कुछ ही मिल पाते हैं। अधिकतर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। कुछ साल पहले मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी दुनिया भर में गायब होने वाले लोगों पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए गहरी चिंता जताई थी। उसका कहना था कि दुनिया में अधिकतर लोगों को जबरन उठा लिया जाता है और उन्हें युद्ध सहित कई अनैतिक कामों में धकेल दिया जाता है। संगठन का कहना है कि सीरिया में साल 2011 से लेकर अब तक लगभग 82,000 लोगों को जबरन गायब कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश लोग सशस्त्र विपक्षी समूहों और खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले सशस्त्र समूह द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद लापता हो गए हैं। वहीं श्रीलंका में 1980 से लेकर अब तक करीब 60,000 से अधिक लोग गायब हो गए हैं।

अगर इतिहास की बात करें तो अर्जेंटीना में बीसवीं शताब्दी में सामूहिक रूप से लोगों के जबरन गायब किए जाने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अंतिम तानाशाही थी। 1976-1983 के बीच दक्षिण अमेरिकी देश में सैन्य शासन के दौरान सुरक्षा बलों ने लगभग 30,000 लोगों का अपहरण किया, जिनमें से कई का अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। इस दौरान व्यापक और व्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर यातनाएं और गैर-न्यायिक हत्याएं शामिल थीं। इनमें कुख्यात मौत की उड़ानें भी शामिल थीं, जिनमें पीड़ितों को सैन्य विमानों या हेलीकॉप्टरों से गिराकर मार डाला गया था। दुनिया भर में कई संगठन लंबे समय से गायब होने वाले लोगों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिल पाई है। इतना जरूर है कि कुछ मामलों में जिम्मेदारों को दोषी ठहराने के लिए अभियान चलाया

गया। इसके बाद कुछ दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में सफलता मिली।

असल में जबरन गुम किए जाने के शिकार वे लोग होते हैं, जो सचमुच गायब हो जाते हैं। वे तब लापता हो जाते हैं, जब उन्हें सड़क या उनके घरों से उठा लिया जाता है। अधिकतर मामलों में इन गुमशुदगी से इनकार किया जाता है या यह बताने से मना कर दिया जाता है कि वे कहां हैं। कभी-कभी ये गुमशुदगी सशस्त्र गैर-सरकारी तत्वों जैसे सशस्त्र विपक्षी समूहों द्वारा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह एक अपराध है। इन लोगों को अक्सर रिहा नहीं किया जाता और उनका क्या हुआ, यह भी अनिश्चित रहता है। बताया जाता है कि इन लापता लोगों को गलत कामों में धकेल दिया जाता है। लड़कियों को वेश्यावृत्ति में भेज दिया जाता है। बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंसा दिया जाता है। इन लापता लोगों को अक्सर यातनाएं दी जाती हैं। इनमें से कई मारे जाते हैं या फिर मारे जाने के भय में जीते हैं। वे जानते हैं कि उनके परिवार को पता नहीं है कि वे कहां हैं और उनकी मदद की संभावना बहुत कम है। भले ही वे मौत से बच जाएं और रिहा हो जाएं, लेकिन शारीरिक और मानसिक घाव उनके साथ रह जाते हैं।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जबरन गुमशुदगी एक वैश्विक मुद्दा है। दुनिया के कई देशों में ऐसे लोगों का इस्तेमाल अक्सर समाज में आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में किया जाता है। इससे उत्पन्न असुरक्षा और भय की भावना केवल गुमशुदगी के करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि समुदायों और पूरे समाज को प्रभावित करती है। कभी सैन्य तानाशाहों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली ये गुमशुदगियां अब दुनिया के हर क्षेत्र में और विभिन्न परिस्थितियों में घटित होती हैं। ये आमतौर पर आंतरिक संघर्षों में विशेष रूप से राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही सरकारों या सशस्त्र विपक्षी समूहों द्वारा की जाती हैं। लापता लोगों के परिवार और मित्र मानसिक पीड़ा से जूझते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका बेटा या बेटी, मां या पिता जीवित हैं या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें कहां रखा गया है या उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।

लापता लोगों की खोज पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। यह न जानना कि उनका प्रियजन कभी वापस लौटेगा या नहीं, अक्सर रिश्तेदारों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देता है। रिपोर्ट कहती हैं कि वैश्विक स्तर पर जबरन गुम किए जाने के शिकार लोगों में से अधिकांश पुरुष होते हैं। हालांकि गुम होने के बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए संघर्ष का नेतृत्व अक्सर महिलाएं ही करती हैं। इस दौरान वे खुद को धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा के जोखिम में डालती हैं। इसके अलावा लापता व्यक्ति अक्सर परिवार का मुख्य कमाने वाला होता है। वही एकमात्र व्यक्ति होता है, जो फसल उगा सकता है, नौकरी कर सकता है या फिर पारिवारिक व्यवसाय चला सकता है। कुछ राष्ट्रीय कानूनों के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण-पत्र के बिना पेंशन या अन्य सहायता प्राप्त करना संभव नहीं होता।

रिपोर्ट कहती हैं कि सैन्य रूप से संचालित देशों में जबरन गायब किए जाने के कई पीड़ितों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। लापता व्यक्ति को यातना का भी उच्च जोखिम होता है, क्योंकि वह कानून की सुरक्षा से पूरी तरह बाहर हो जाता है। कानूनी उपायों तक पहुंच न होने के कारण पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से असहाय और भयावह स्थिति में होता है। जबरन लापता किए गए पीड़ितों को यौन हिंसा या हत्या जैसे अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों का भी उच्च जोखिम होता है। हाल ही के वर्षों में भारत में लापता लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। केरल, गुजरात और मध्यप्रदेश से कई मामले सामने आने के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के लापता होने की खबर आना एक बड़े संकट की ओर इशारा है। केरल में तो लापता लड़कियों पर द केरल फाइल्स जैसी फिल्म भी बनाई जा चुकी है।

गायब होने वाले लोगों पर दुनिया भर के संगठन अभियान चला रहे हैं। उनकी मांग है कि सबसे पहले मामले की निष्पक्ष जांच करें। पर्याप्त सबूत मौजूद होने पर आपराधिक जिम्मेदारी के संदिग्धों पर सामान्य नागरिक अदालतों के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई में मुकदमा चलाएं। जबरन गायब होने को राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध घोषित किया जाए। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित दंडों से दंडनीय बनाया जाए। ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करें और पीड़ितों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों और अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों को मुआवजा मिले। इसमें क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, पुर्नस्थापन और यह गारंटी शामिल हो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। किसी भी प्रकार के क्षमादान कानून या दंड से मुक्ति दिलाने वाले किसी भी अन्य उपाय जैसे कि परिसीमा अधिनियम आदि को निरस्त करें। हर हाल में उनके मानवाधिकारों की रक्षा करें और उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की जाए।

समृद्ध जल साधनों के बीच प्यासा आदिवासी समाज

मुद्दा

राज कुमार सिन्हा

लेखक बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के प्रतिनिधि हैं।

डिंडोरी को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिले में मौजूदा वर्ष में पेयजल और सिंचाई के लिये उपलब्ध पानी की कमी का संकट गहराया है, खासकर आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में जल संसाधनों के विनियमन और उपयोग पर नियंत्रण लगाया गया है। यह आदेश 10 फरवरी से 30 जून 2026 तक लागू रहेगा, जिसमें पानी के अनावश्यक दोहन पर रोक और संरक्षण-उन्मुख व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी नलकूप,बोरवेल एवं हैंडपम्प के लिए अनधिकृत खनन और ड्रिलिंग पर रोक जैसे कदम भी प्रशासन ने उठाए हैं ताकि जल स्तर और उपलब्धता को बचाया जा सके।

डिंडोरी और आसपास के आदिवासी-ग्रामीण जिलों में पहले से भूजल स्तर गिर रहा है और पेयजल की उपलब्धता सीमित है। मौसमी स्रोतों पर अत्यधिक दबाव और वर्षाजल संचयन की कमी के कारण प्रशासन ने जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये इस आदेश का सहारा लिया है ताकि गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की समस्याएं और गंभीर न हों।डिंडोरी और आसपास के आदिवासी-ग्रामीण जिलों में पहले से भूजल स्तर गिर रहा है और पेयजल की उपलब्धता सीमित है। मौसमी स्रोतों पर अत्यधिक दबाव और वर्षाजल संचयन की कमी के कारण प्रशासन ने जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये इस आदेश का सहारा लिया है ताकि गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की समस्याएं और गंभीर न हों।

मध्यप्रदेश को देश का सबसे बड़ा आदिवासी आबादी वाला राज्य कहा जाता है। आदिवासी समुदाय सदियों से जंगल, नदी और पहाड़ियों के साथ सहजीवन में रहे हैं। विडंबना यह है कि आज वही समुदाय पानी की सबसे गंभीर असुरक्षा का सामना कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर आदिवासी अंचल आज पानी के लिए जूझते दिखाई देते हैं।

मध्यप्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार,

बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, सिंगरौली और शिवपुरी (सहरिया क्षेत्र) जैसे जिले मुख्यतः आदिवासी हैं। ये क्षेत्र या तो पथरीली पहाड़ियों, घने जंगलों या पठारी भूभाग पर बसे हैं, जहां जल का प्राकृतिक संचयन कठिन होता है।आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल का मुख्य आधार झरने, छोटे नाले, कुएं और हैंडपंप हैं। गर्मियों में ये स्रोत सूख जाते हैं, जिससे कई गांवों में तीन-चार महीने गंभीर जल संकट रहता है।गहरे नलकूप आधारित जल व्यवस्था आदिवासी अंचलों के भूगर्भ के अनुकूल नहीं है। नतीजतन, बड़ी संख्या में हैंडपंप कुछ वर्षों में ही सूख जाते हैं, जिससे सरकारी निवेश व्यर्थ हो जाता है।कई आदिवासी क्षेत्रों में भूजल में फ्लोराइड, आयरन और नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इससे दंत रोग, हड्डियों की विकृति और पेट से जुड़ी बीमारियां आम हैं, लेकिन जांच और उपचार की सुविधाएं सीमित हैं।नर्मदा घाटी, सिंगरौली, बालाघाट और मंडला जैसे क्षेत्रों में बांध, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं ने आदिवासियों को उनके पारंपरिक जल स्रोतों से अलग कर दिया है। विस्थापन के बाद बसाए गए गांवों में अक्सर स्थायी जल व्यवस्था नहीं होती, जिससे पानी की समस्या और गहरी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून, कम अवधि में तेज़ वर्षा और लंबे सूखे ने आदिवासी कृषि और जल स्रोतों दोनों को प्रभावित किया है। पहले जिन झरनों में सालभर पानी रहता था, वे अब सिर्फ मानसून तक सीमित हो गए हैं।

आदिवासी समाज के पास पारंपरिक जल संरक्षण का समृद्ध ज्ञान रहा है,जैसे पहाड़ी ढलानों पर छोटे बांध, झिरिया, डबरा, जैसे स्थानीय जल ढांचे प्रमुख हैं। जंगल संरक्षण के माध्यम से जल संरक्षण की आधुनिक नीतियों में इस ज्ञान को नजर अंदाज किया गया, जिससे समाधान टिकाऊ नहीं बन पाए। इसलिए विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन के अन्तर्गत ग्रामसभा आधारित जल योजना, जहां पानी को सामुदायिक संसाधन मानना, झिरिया, तालाब, झरनों और छोटे बांधों का संरक्षण, कम गहराई वाले कुएं, वर्षाजल संचयन और गुरुत्व आधारित जल प्रणालियां विकसित करने का प्रयास करना और जल समितियों में आदिवासी महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने जैसे प्रयास प्रमुख हैं। मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पानी की समस्या केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि नीतिगत उपेक्षा और विकास के असंतुलित मॉडल का परिणाम है। जब तक आदिवासी समाज को जल प्रबंधन का केंद्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक 'हर घर जल' का सपना इन अंचलों में अधूरा ही रहेगा।आदिवासी समाज को पानी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनसे उनका पानी छीना जा रहा है, यह सच्चाई स्वीकार किए बिना समाधान संभव नहीं है। मध्यप्रदेश में तेजी से गिरता भूजल न केवल किसान समुदाय के लिए चिंता का विषय है, बल्कि शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन के लिए जल सुरक्षा संकट का संकेत देता है।

मध्यप्रदेश में लगभग 58.75 से 60 प्रतिशत भूजल का दोहन हो चुका है, जो राज्य को बढ़ते जल संकट की ओर ले जा रहा है।कृषि के लिए भूजल उपयोग लगभग 90 प्रतिशत है, जबकि घरेलू उपयोग में 9 प्रतिशत और औद्योगिक उपयोग के लिए 1 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि कृषि आधारित भूजल दोहन सबसे बड़ा कारण है।ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, जिससे लोगों को बड़े-बड़े टैंकर और ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ रही है। मध्यप्रदेश के भूजल भंडार की गिरावट सामयिक समस्या नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक आपदा बन चुकी है। केवल भूमि-स्तर पर नीतिगत संवर्धन, सूचना-आधारित प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी से ही भविष्य में पानी की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।

डिंडोरी में जल संकट 'संभावना' नहीं, 'वर्तमान स्थिति' बन चुका है। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और कमजोर रिचार्ज व्यवस्था असफल हो रही है। यदि अभी नियंत्रण नहीं किया गया, तो गर्मी के समय में पेयजल आपातकाल बन सकता है। यह पहली बार है जब प्रशासन ने पानी को कानून और अनुशासन के दायरे में लाने की कोशिश की है। यदि इस आदेश को केवल प्रतिबंध मानकर टाल दिया गया, तो संकट बढ़ेगा। लेकिन यदि इसे जल-अनुशासन की शुरुआत माना गया, तो डिंडोरी एक उदाहरण बन सकता है।

पुलिसः चाल, चरित्र और चेहरा

दृष्टिकोण

विजय जोशी

लेखक भेल भोपाल के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक हैं।

दूर रहकर जो नजर आते थे सीधे साधे
उनको नजदीक से देखा तो सितमगर निकले

आज़ादी उपरांत जिन चुनौतियों से हम आज भी जूझ रहे उनमें सर्वोपरि है भ्रष्टाचार। इस संदर्भ में हाल ही में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा भ्रष्टतम विभागों की सूची में सिरमौर खिताब प्राप्त विभाग है पुलिस। रिश्वतखोरी, फर्जी केस, अवैध वसूली के लिये शीर्ष पर। भ्रष्टाचार, अनाचार की एक मुकम्मल पहचान। यह तो हुई पहली बात।

दूसरी बात है नेताओं से पुलिस का गठजोड़। 'मेड फार इच अदर' का यह संगम सुविधानुसार एक दूसरे का सीढ़ी के समान उपयोग करते हुए अपने स्वार्थ की सदैव से सिद्धि करता रहा है । कहा जाता है हमारे प्रदेश में एक दौर में थानों की नीलामी हुआ करती थी। अपने गॉड फादर राजनेताओं की सेवा तथा कमाई कर सकने वाली क्षमता जैसी विशेषता उनके चरित्र में चार चाँद लगा दिया करती थी। ऐसे में इस समुदाय में सीमित मात्रा में उपलब्ध सज्जन पुलिसवाले सदैव समय की सूली पर दृष्टिगोचर होते रहे हैं।

ईश्वर कृपा से मुझे परदेस भ्रमण के अनेक अवसर प्राप्त हुए एवं वहां जिस पुलिस व्यवहार के दिग्दर्शन हुए उसकी एक छोटी सी बानगी साझा करने का विचार इस समय मन में है

1) लंदन पुलिस : एक दशक पूर्व की घटना है यह। लंदन की भूमिगत ट्यूब ट्रेन विश्वविख्यात एवं अनूठी है । बेटी यात्रा प्रक्रिया समझाकर अपने नगर लौट गई थी। संध्या काल अपने दम पर यात्रा का आनंद प्राप्त करने प्लेटफार्म पर पहुंचे टिकट लेकर और अगली ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही एक ट्रेन आई तो अपनी हिन्दुस्तानी आदत के अनुसार मैं अंदर प्रवेश कर गया गंतव्य जानकारी हेतु। अचानक गेट बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। छोटी बेटी और पत्नी प्लेटफार्म पर। मैं हिंदी अंग्रेजी और दोनों के सफर में। देश पराया, परिवार प्लेटफार्म पर। नर्वस हो जाने का पूरा इंतजाम। फिर मन शांत किया। सौजन्यपूर्ण सहयात्रियों ने ढांढस बंधाते हुए मार्गदर्शन दिया। तदनुसार अगले ही स्टेशन पर उतरकर मैंने विपरीत दिशा ट्रेन पकड़ी तथा पूर्व स्थान पर आकर उतर गया। आने पर एक सुखद आश्चर्य मेरी प्रतीक्षा में था। एक पुलिस वाला जिन्हे वहां कॉप कहा जाता है और जिसे शायद ऐसे ही अप्रत्याशित घटनाक्रम पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, तुरंत निकट आया व परिवार को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं,

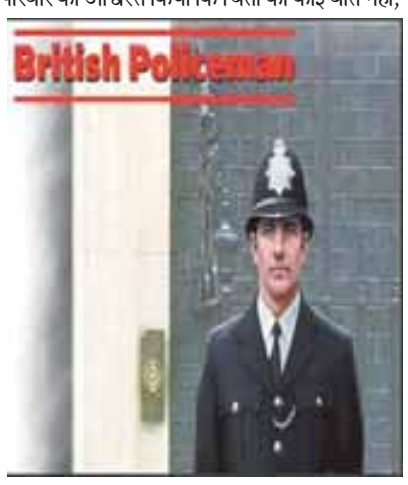

अगले कुछ ही पलों में गृह स्वामी लौट आयेंगे और जब तक वे नहीं आते वह खुद साथ रहेगा ।

आगे की बात बहुत सरल थी। मन में हनुमान चालीसा का सतत पाठ करते हुए जब मैं लौटा तो परिवार की सांस में सांस आई। पूरे घटनाक्रम से अवगत हुआ और जब धन्यवाद ज्ञापन हेतु उद्यत हुआ तो उस सज्जन कॉप का कहीं अता पता नहीं था। वह अगले मिशन पर प्रस्थान कर चुका था कर्तव्य की शिला पर अपनी निस्वार्थ सेवा की छाप छोड़कर बगैर किसी आभार प्रदर्शन जैसी औपचारिकता निभाने का अवसर दिये। मुझे उसे धन्यवाद तक न कह पाने का दर्द आज तक सालता है । अब क्या कहेंगे इस सौजन्य, सहायता और सहृदयता को । (क्रमशः)

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

श्याम यादव

(व्यंग्यकार)

समझते हो ... डील का हिसाब-किताब!

मुसद्दीलाल के घर के बाहर लगा बोर्ड इन दिनों मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा था। जो भी उधर से गुजरता, चलते-चलते एक बार नज़र डाल ही देता 'हमारे यहाँ डील करना सिखाया जाता है।' कुछ लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते, कुछ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते। दो-चार ऐसे भी थे जो ठहरकर सोचते कि मुसद्दीलाल ने यह कौन-सा नया काम शुरू कर दिया। ज़माना ऐसा है कि आजकल सब कुछ सिखाया जाता है मेहंदी से लेकर ब्यूटी पार्लर, बोलने का ढंग, चुप रहने की कला और बेचने का तरीका। ऐसे में डील सिखाने की बात पहली नज़र में लोगो को चकित ज़रूर करती थी, लेकिन ज़्यादा देर तक अटपटी नहीं लगती थी।

धीरे-धीरे मोहल्ले में यह मान लिया गया कि मुसद्दीलाल समझदार आदमी हैं। टीवी पर बहस देखते हैं, अख़बार पूरा पढ़ते हैं और बातचीत में वैश्विक परिस्थिति, रणनीतिक मजबूरी और 'लॉन्ग टर्म फ़ायदा' जैसे शब्द सहजता से जोड़ देते हैं। जब भी किसी चीज़ के दाम बढ़ते, वे गंभीर होकर कहते 'अब दुनिया बदल रही है। लोग सिर हिलाकर मान लेते कि बात बड़ी है, हमारी समझ से बाहर है। उनका बोर्ड उसी समझदारी का सार्वजनिक प्रमाण माना जाने लगा।'

एक सुबह मैंने देखा, बोर्ड के नीचे एक आदमी खड़ा है। हाथ में सब्ज़ी की थैली, चेहरे पर रोजमर्रा का हिसाब साफ़ झलक रहा था। वह बोर्ड को ऐसे पढ़ रहा था जैसे कोई सरकारी सूचना हो। उसने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा, फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला 'सीखना तो ठीक है, पर निभाएगा कौन?' उसकी आवाज़ में न शिकायत थी, न कटाक्ष। बस एक साधारण-सा सवाल था, जैसा आदमी अपने आप से पूछ लेता है। वह बोला 'डील ऊपर होती है, असर

नीचे आता है। कभी दाम बढ़ जाते हैं, कभी काम घट जाता है। हर बार समझाया जाता है कि ज़रूरी था, हालात ऐसे थे, विकल्प नहीं था।' उसने सब्ज़ी की थैली को थोड़ा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे उसे अपने सवाल का जवाब पहले से पता हो।

थोड़ी देर बाद एक और राहगीर आया। उसने बोर्ड पढ़ा और हँसते हुए कहा 'अब तो सब डील ही है, नौकरी भी डील, व्यापार भी डील। आदमी भी डील करके ही टिक रहा है।' बात वहीं खत्म हो गई, जैसे आजकल ज़्यादातर बातें खत्म हो जाती हैं अधूरी, हल्की हँसी के साथ। मुसद्दीलाल बाहर नहीं आए। शायद आने की ज़रूरत भी नहीं थी। बोर्ड अपना काम कर रहा था चुपचाप, लगातार। वह न किसी को बुला रहा था, न रोक रहा था। बस खड़ा था, जैसे हालातों की एक स्थायी सूचना।

आम आदमी अपनी थैली संभालकर आगे बढ़ गया अपने खर्च, अपने हिसाब और अपनी चुप्पी के साथ। उसे न डील की भाषा समझनी थी, न शर्तों की बारीकी। उसे बस इतना पता था कि हर डील के बाद कुछ न कुछ उसी के हिस्से में आता है। वह उसे स्वीकार करता चलता है। बिना सवाल, बिना शोर। क्योंकि डील करना एक हुनर है और उसका हिसाब, अक्सर वही चुकाता है, जो डील में शामिल ही नहीं होता।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि

सुरेंद्र शर्मा

लेखक मध्यप्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं।

एकात्म मानव दर्शन को साकार कर रही नरेंद्र मोदी सरकार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने भारत के स्व को पहचानकर भारतीयता के आधार पर भारत के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देखा जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता की और कहा बिना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार हुए राष्ट्र का अपने बल पर खड़ा होना मुश्किल है 'अंत्योदय से ही राष्ट्रोदय' संभव है का मंत्र देने वाले आज की भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणापुंज और जनसंघ के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नियति ने 11 फ़रवरी 1968 को देश से छीन लिया पर उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र सरकार एवं देश के 19 राज्यों की भाजपा एवं भाजपा गठबंधन की सरकारें दीनदयाल जी के स्वप्न को साकार कर रही हैं। एकात्म मानव दर्शन का मूल उद्देश्य मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी न मानकर उसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वित रूप मानना है। यह दर्शन भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित है। वर्तमान समय में यदि भारत की राजनीति में इस दर्शन की व्यावहारिक अभिव्यक्ति देखी जाए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इसके तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस दर्शन के अनुसार विकास केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुँचाना ही इसका उद्देश्य है, जिसे 'अंत्योदय' कहा गया है।

भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो उसका आधार केवल भारत का ही चिंतन हो सकता है, पश्चिम के आधार पर चलकर हम केवल पश्चिमी देशों के पिछलग्गु तो बन सकते हैं हम दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकते,भारत को अपने स्व को पहचानकर आगे बढ़ना होगा। यह चिंतन आधुनिक भारत के समस्त मनीषियों का रहा है इस चिंतन को 'एकात्म मानव दर्शन' के रूप में प्रतिपादित करने वाले थे भारतीय जनसंघ के तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने भारत के स्व को पहचानकर भारतीयता के आधार पर भारत के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देखा जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता की और कहा बिना समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार हुए राष्ट्र का अपने बल पर खड़ा होना मुश्किल है 'अंत्योदय से ही राष्ट्रोदय' संभव है का मंत्र देने वाले आज की भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणापुंज और जनसंघ के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नियति ने 11 फ़रवरी 1968 को देश से छीन लिया पर उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र सरकार एवं देश के 19 राज्यों की भाजपा एवं भाजपा गठबंधन की सरकारें दीनदयाल जी के स्वप्न को साकार कर रही हैं।

एकात्म मानव दर्शन का मूल उद्देश्य मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी न मानकर उसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वित रूप मानना है। यह दर्शन भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित है। वर्तमान समय में यदि भारत की राजनीति में इस दर्शन की व्यावहारिक अभिव्यक्ति देखी जाए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इसके तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस दर्शन के अनुसार विकास केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुँचाना ही इसका उद्देश्य है, जिसे 'अंत्योदय' कहा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का साधन माना है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का नारा एकात्म मानव दर्शन की भावना को ही प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की योजनाएँ एकात्म मानव दर्शन की अंत्योदय अवधारणा को साकार करती हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक कुल लाभार्थी संख्या लगभग 57.11 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। इन खातों के खुलने के बाद सरकार की योजनाओं से मिलने मिलने वाली राशि सीधे हितग्राहियों को प्राप्त हो रही है और बिचौलियों से जनता को राहत मिली है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएँ से मुक्ति और सम्मानजनक जीवन मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लगभग 10.33 करोड़ परिवार देश भर में उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना भारत की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को कैशलेस और मानक उपचार प्रदान करना है। अब तक लगभग 40.45 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो लगभग 14.69 करोड़ परिवारों को कवर करते हैं। देश भर के गरीब परिवारों तक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा पहुँच चुकी है, जिससे वे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कैशलेस तौर पर अस्पतालों में प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश में 30,000 से अधिक अस्पताल (सरकारी + निजी) योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, ताकि लाभार्थी आसानी से इलाज करवा सकें।

ये योजनाएँ केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव भी उत्पन्न करती हैं, जो एकात्म मानव दर्शन का मूल तत्व है।

एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देता है। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी सोच का आधुनिक रूप

है। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक,तकनीकी और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान–'वोकल फॉर लोकल'– भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सांस्कृतिक स्वाभिमान को भी सुदृढ़ करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भी जुड़ा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आयात घटता है और देश की अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3,759.46 करोड़ का बजट मिला है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटन, प्रदूषण नियंत्रण (जैसे वायु और जल प्रदूषण से निपटने वाली योजनाओं) के लिए 1,091 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर जोर देना प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की भावना को दर्शाता है।

एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा मानता है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण पर विशेष ध्यान दिया है। नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास/पुनर्निर्माण इन परियोजनाओं में मंदिरों की पुरानी संरचनाओं की बहाली, परिसर का विस्तारीकरण, सुधार, एवं पर्यटन-आस्था केंद्र के रूप में विकास शामिल है–जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक शिक्षा और समग्र विकास पर दिया गया बल एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित ही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीति को नैतिकता से जुड़ा कर्म माना था। मोदी सरकार द्वारा 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अवधारणा इसी सोच को दर्शाती है। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' नरेन्द्र मोदी सरकार का एक प्रमुख शासन दर्शन है। न्यूनतम सरकार इसका अर्थ है– सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप कम हो,लेकिन शासन की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और जवाबदेही अधिक हो। इस विचार का मूल उद्देश्य है कि सरकार नियंत्रक नहीं, बल्कि सुविधादाता की भूमिका निभाए। जनता के जीवन में सरकार की उपस्थिति कम दिखे, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शासन तेज़, पारदर्शी और प्रभावी हो। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर देकर सरकार ने शासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने का प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में एकात्म मानव दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। चाहे वह अंत्योदय हो, आत्मनिर्भरता हो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो या संतुलित विकास–इन सभी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की छाया दिखाई देती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज हमारे बीच नहीं है पर उनके बताए मार्ग पर चलकर 'एकात्म मानव दर्शन' के सिद्धांत और अंत्योदय से राष्ट्रोदय के संकल्प का आज आज हम साकार होता हुआ देख रहे हैं।

कछुओं की तस्करी

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास)

दीपक ने इंसानियत का दीप जलाकर क्या गुनाह किया ?

देश में घटनाएँ इतनी तीव्रता से बदल रही हैं कि कभी-कभी लगता है जैसे ''जनतंत्र'' का ''तंत्र'' कहीं नींद में है, अथवा जीवंत न होकर लगभग मौन है। जब न्याय का तराजू झुकता दिखाई दे, तो ''आग लगे बस्ती में, मुनादी करे दरोगा'' जैसी स्थिति बनती प्रतीत होती है।

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में 46 वर्षीय जिम प्रशिक्षक दीपक कुमार कश्यप ने जो किया, वह सांप्रदायिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से असाधारण कहा जा सकता है। उन्होंने 75 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद की सार्वजनिक रूप से रक्षा की।

26 जनवरी 2026 को कुछ संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता ''बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर'' नामक दुकान पर पहुँचे और ''बाबा'' शब्द को हिंदू आस्था से जोड़ते हुए नाम परिवर्तन की मांग की। जबकि ''बाबा'' शब्द विभिन्न धार्मिक परंपराओं में प्रचलित है–''पीर बाबा'' इसका उदाहरण है, जहाँ सभी धर्मों के लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसी बीच दीपक कश्यप ने अपने साथी विजय के साथ मामले में बीच-बचाव किया। जब उनसे नाम पूछा गया, तो उन्होंने स्वयं को ''मोहम्मद दीपक'' बताते हुए कहा–''मैं पहले इंसान हूँ, इंसानियत का धर्म निभाऊँगा।'' यह कथन केवल शब्द नहीं था, बल्कि ''सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे'' जैसी संतुलित संवेदनशीलता का उदाहरण था। स्थिति वहीं शांत हो गई।

घटना के पाँच दिन बाद बाहरी जिलों से आए 30-40 लोगों ने दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, सड़क जाम की और गिरफ्तारी की मांग की। आरोप हैं कि बैरियर तोड़े गए और उनके परिवार को भी धमकाया गया। पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज कीं। आश्चर्य यह कि दीपक और उनके साथी के विरुद्ध गंभीर धाराएँ लगाई गईं, जबकि उपद्रव के आरोपियों में कई अज्ञात रखे गए। दीपक को कई घंटे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। विजय रावत की गिरफ्तारी हुई, परंतु जिन पर खुलेआम उपद्रव के आरोप हैं, उनकी पहचान के बावजूद कार्रवाई शिथिल बताई जा रही है। क्या यह ''उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'' जैसी स्थिति नहीं है? दीपक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उनकी जान को खतरा है और स्थानीय प्रशासन मिलीभगत कर रहा है। उन्होंने अपील की ''मैं रहूं या न रहूं, लेकिन इंसानियत जिंदा रहेगी। मैं नफरत के आगे नहीं झुकूंगा।''

भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ 34 से 44 तक आत्मरक्षा का अधिकार स्पष्ट करती हैं। यदि कोई व्यक्ति या तीसरा नागरिक किसी की जान-माल की रक्षा हेतु तत्काल हस्तक्षेप करता है, तो वह अपराध नहीं बल्कि विधिसम्मत आत्मरक्षा के अधिकार की परिधि में आता है–बशर्ते उसका आचरण अनुपातिक हो।

यहाँ मूल प्रश्न यह है–क्या दीपक का हस्तक्षेप शांति भंग था, या शांति की रक्षा का प्रयास? यदि पुलिस तत्काल प्रभावी ढंग से उपलब्ध न हो, तो नागरिक को सीमित दायरे में हस्तक्षेप का अधिकार है। ऐसे में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करना क्या न्यायसंगत है, या यह '' न्याय की नाव को बीच धारा में डुबोने '' जैसा कदम है?

उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पर स्वतः संज्ञान लेकर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है– चाहे वह महामारी का संकट हो, (कोविड-19 (2020-2021), पर्यावरण का प्रश्न हो (1998) ,जातीय हिंसा के मामले मणिपुर (2023-2024)।

आरजी कार मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या का मामला (2024) हो या फिर मध्याह्न भोजन योजना से मृत्यु और प्रवासी श्रमिक संकट (2020)।

जब न्यायालय ने ÷पत्र÷ (के आधार पर भी संज्ञान लिया है (सुनील बत्रा प्रकरण 1978-80), तो क्या यहाँ, जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव और नागरिक सुरक्षा का प्रश्न है, न्यायिक हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं?

कुत्तों के लिए स्व संज्ञान उच्चतम न्यायालय ले सकता है, तब यहां पर तो एक नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ खड़ा बड़ा प्रश्न सांप्रदायिक सामुदायिक सद्भाव के साथ श्सींट के मूल्य का प्रश्न है, जिसे बनाए रखने के लिए एक नागरिक ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर तथा स्वयं व परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालकर दूसरे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की। कहीं दीपक का यह प्रयास ÷नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर न रह जाए÷। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ''दिखना'' भी चाहिए।

दीपक ने एक बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए ÷अपना सर ओखली में दिया÷। इसे दीपक के बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या पृष्ठभूमि के समाज में सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। आज जब छोटी-छोटी बातों पर ''चिंगारी से शोला'' बनते देर नहीं लगती, तब किसी का आगे आकर आग पर पानी डालना निस्संदेह साहसिक कदम है। ऐसे मानवीय कृत्य को यदि संरक्षण नहीं मिलेगा, तो भविष्य में कोई भी नागरिक उपद्रवी सांप्रदायिक ''भीड़'' के सामने खड़ा होने से पहले सौ बार सोचेगा। और तब समाज में ''जंगलराज'' की आशंका को कौन टालेगा?

यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस मूल्य का है जिसे हम ''सह-अस्तित्व'' कहते हैं। यदि प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करे, दोषियों पर समान रूप से कार्रवाई हो और निर्दोष को संरक्षण मिले–तो यही लोकतंत्र की असली जीत होगी। न्यायालय से अपेक्षा है कि यदि आवश्यक हो तो वह अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप मार्गदर्शन दे। क्योंकि अंततः राष्ट्र की मजबूती कानून की निष्पक्षता और समाज की संवेदनशीलता से ही तय होती है। दीपक का दीप यदि इंसानियत के आले में जला है, तो उसे आँधी से बचाना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तभी हम एकजुट होकर अपने देश के गौरवशाली इतिहास को बचा पाएंगे। अन्यथा जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध।

विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

विज्ञान-अनुसंधान में आधी आबादी की निर्विवाद भूमिका

विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदमों की बात करें, तो मंगल मिशन की सफलता से लेकर नासा और नोबेल पुरस्कार तक भारतीय महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। विज्ञान के वैश्विक स्तर पर भी भारतीय महिलाओं की धूम है। ये सिलसिला अब इसलिए भी रूकने वाला नहीं क्योंकि सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर महिलाएं दिनोंदिन विज्ञान की दुनिया में अकल्पनीय कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। एकाध दशकों के भीतर विज्ञान क्षेत्र और उसके विषय में महिलाओं की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी के तौर पर उभरी है। आधी आबादी ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपना क्रांतिकारी योगदान देकर अपने दम पर पुरूषों के साथ कदम ताल मिलाया है। मैरी क्यूरी से लेकर भारतीय अंतरिक्ष मिशनों तक, महिलाओं ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अपनी प्रतिभा सिद्ध की हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,628 करोड़ रुपये आवंटित इसलिए किए थे, ताकि इस क्षेत्र में धन की कमी न आए। विज्ञान क्षेत्र में पुरूषों के तौर पर स्टीफन हॉकिंग, आईजैक न्यूटन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन जैसे महान पुरुष वैज्ञानिकों की ही छवि लोगों के जेहन में उभरती थी। पर, अब भारत में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष-2018-19 की विभिन्न शोध परियोजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी तकरीबन 28 से 30 फीसदी तक बढ़ीं। 2024-24 के आंकड़ों में और इजाफा हुआ है। गति अगर यूं ही बरकरार रही, तो साल 2047 में जब भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, तब विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी हो जाएगी।

आधी आबादी को समर्पित आज का दिन कई मायनों में खास है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए सालाना 11 फरवरी को 'विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणितज्ञ क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ाना और लैंगिक असमानता को दूर करना था। आज 11 फरवरी 2026 में इस दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष-2025 की थीम 'भविष्य को आकार देने के लिए प्रगति की रूपरेखा तैयार करना' थी। वहीं, इस साल की थीम 'अभी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है पर केंद्रित है।

विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदमों की बात करें, तो मंगल मिशन की सफलता से लेकर नासा और नोबेल पुरस्कार तक भारतीय महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। विज्ञान के वैश्विक स्तर पर भी भारतीय महिलाओं की धूम है। ये सिलसिला अब इसलिए भी रूकने वाला नहीं? क्योंकि सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर महिलाएं दिनोंदिन विज्ञान की दुनिया में अकल्पनीय कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। एकाध दशकों के भीतर विज्ञान क्षेत्र और उसके विषय में महिलाओं की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी के तौर पर उभरी है। आधी आबादी ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपना क्रांतिकारी योगदान देकर अपने दम पर पुरूषों के साथ कदम ताल मिलाया है। मैरी क्यूरी से लेकर भारतीय अंतरिक्ष मिशनों तक, महिलाओं ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अपनी प्रतिभा सिद्ध की हैं।

केंद्र सरकार ने 2024-25 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,628 करोड़ रुपये आवंटित इसलिए किए थे, ताकि इस क्षेत्र में धन की कमी न आए। विज्ञान क्षेत्र में पुरूषों के तौर पर स्टीफन हॉकिंग, आईजैक न्यूटन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन जैसे महान पुरुष वैज्ञानिकों की ही छवि लोगों के जेहन में उभरती थी। पर, अब भारत में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष-2018-19 की विभिन्न शोध परियोजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी तकरीबन 28 से 30 फीसदी तक बढ़ीं। 2024-24 के आंकड़ों में और इजाफा हुआ है। गति अगर यूं ही बरकरार रही, तो साल 2047 में जब भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, तब विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी हो जाएगी।

महिलाओं के लिए भारत अब बदल चुका है। क्योंकि वैश्विक औसत के हिसाब से विज्ञान क्षेत्र में भारतीय महिलाएं की रूचि ज्यादा बढ़ी है। हिंदुस्तान में लड़कियों को अब कम उम्र से ही स्टृम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा है। यही कारण है कि स्टेम

शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी अब लगभग 43 प्रतिशत तक जा पहुंची है। केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में इंटरशिप, छात्रवृत्तियां और अन्य 11 पीठों का गठन महिला शोधकर्ताओं को बढ़ाने मकसद से शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार में इसका अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। मंत्रालय का नाम है 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान'। एक जमाना था, जब विज्ञान जैसे क्षेत्रों में गिनी चुनी महिलाओं की ही आमदगी होती थी। पर, अब इसरो के चंद्रयान और मंगलयान मिशनों की सफलता में भारतीय महिला वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान भी दिखने लगा है।

आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर, असिमा चटर्जी पहली कैंसर और मिर्गी शोध, सुषमा घोष पहली चिकित्सा विज्ञान और जानकी अम्माल ने गन्ने की हाइब्रिड प्रजातियों के विकास में जो योगदान दिया, उसे कोई नहीं भूल सकता। वहीं, अन्ना मणि का सौर विकिरण और ओजोन परत के क्षेत्र में दिया उल्लेखनीय कार्य सदैव सराहनीय रहेगा। इन महिलाओं ने ये सफलताएं उस समय हासिल की थी जब महिलाओं को घरों की चारदीवारी में कैद करके रखा जाता था। बाहर निकले आजादी तक नहीं होती थी। भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने केवल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया, बल्कि गणित, अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में दमदार प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं के संबंध में युवा पीढ़ी को जानना चाहिए।

वैश्विक पटल पर भी भारतीय महिलाओं ने अपने हुनर का लोहा अपनाया। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जानता है। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं जिसने 376 घंटे 34 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने धरती के 252 चक्कर लगाए थे। 1 फरवरी 2003 को हुई अंतरिक्ष इतिहास की एक मनहूस दुर्घटना में कल्पना चावला सहित सातों अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। वही, सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। सुनीता विलियम्स ने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उनसे प्रेरणा लेकर भारतीय महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में आ रही हैं।

विशेष लेख

सय्यद असीम अली

परीक्षा और करियर - दबाव नहीं, दिशा चाहिए

डर को पीछे छोड़ो, लक्ष्य को आगे रखो

12वीं कक्षा की परीक्षा छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है। यही वह समय होता है जब एक छात्र को यह तय करना होता है कि आगे उसे किस दिशा में जाना है। सही करियर का चुनाव केवल अच्छी नौकरी या सैलरी पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसंतोष, सामाजिक सम्मान और भविष्य की स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसलिए एजुकेशन और करियर को लेकर लिया गया निर्णय जीवन की नींव तय करता है।

परीक्षा को उत्सव की तरह लेने का संदेश

जैसे ही परीक्षा का माह शुरू होता है, अधिकतर छात्रों में तनाव बढ़ने लगता है। नींद कम हो जाती है, मन घबराता है और बार-बार यही डर रहता है कि कहीं तैयारी अधूरी न रह जाए। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि टेंशन लेने से पढ़ाई बेहतर नहीं होती, बल्कि फोकस कमजोर हो जाता है। इसलिए छात्रों को सबसे पहले मानसिक रूप से खुद को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए।

परीक्षा के समय सही टाइम टेबल बनाना बेहद ज़रूरी है। पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर रोज़ाना पढ़ाई करें। कठिन विषय सुबह पढ़ें जब दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और आसान विषय रात में दोहराएँ। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला साधन है।

स्वस्थ दिनचर्या भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई। पूरी नींद लें, समय पर भोजन करें और रोज़ थोड़ा-सा व्यायाम या वॉक जरूर करें। इससे दिमाग तरोताज़ा रहता है और याद करने की क्षमता बढ़ती है। बार-बार दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें, क्योंकि हर छात्र की क्षमता अलग होती है।

डिग्री के आगे स्किल- जीत उन्हीं की जो खुद को अपग्रेड करें

आज का दौर केवल डिग्री का नहीं, बल्कि स्किल का है। पहले समय में अच्छी डिग्री मिल जाना ही सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है। अब कंपनियां केवल यह नहीं देखतीं कि आपने क्या पढ़ा है, बल्कि यह देखती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, सोचने की क्षमता और काम करने की शैली ही आपकी असली पहचान बनती है।

टेक्नोलॉजी के विकास ने नौकरियों का स्वरूप बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं, जिनमें डिग्री से ज्यादा स्किल की मांग है। वहीं कई पारंपरिक नौकरियां धीरे-धीरे खत्म भी हो रही हैं। ऐसे में वही छात्र आगे बढ़ पाएंगे जो समय के साथ खुद को अपडेट करते रहेंगे।

आज सीखने के अवसर हर जगह हैं - ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, इंटर्नशिप, वर्कशॉप और प्रोजेक्ट्स। जो छात्र पढ़ाई के साथ-साथ नई चीज़ें सीखते हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रोजगार की संभावना भी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डिग्री एक दरवाज़ा है, लेकिन स्किल वह चाबी है जो उस दरवाज़े को खोलती है। जीत उन्हीं की है, जो लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं।

भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत विशाल है। वर्तमान में देश में लगभग 24.8 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और 14.7 लाख से अधिक स्कूलों में करीब 1 करोड़ शिक्षक कार्यरत हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है और केवल डिग्री के भरोसे आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। हर छात्र को खुद को अलग साबित करना होगा।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि करीब 67 प्रतिशत छात्र पढ़ाई और करियर को लेकर मानसिक दबाव महसूस करते हैं, लेकिन 85 प्रतिशत छात्र किसी से मदद या काउंसलिंग नहीं लेते। यही कारण है कि बहुत से छात्र अंदर ही अंदर घबराते रहते हैं और जल्दबाज़ी में गलत फैसले कर बैठते हैं।

आज की एक बड़ी समस्या यह है कि छात्र बिना करियर प्लानिंग के आगे बढ़ जाते हैं। लगभग 90 प्रतिशत भारतीय छात्र बिना सही मार्गदर्शन के करियर चुनते हैं, जबकि केवल 10 प्रतिशत छात्रों को प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग मिल पाती है। बाद में यही छात्र कहते नजर आते हैं - 'काश पहले सही सलाह मिल जाती।'

करियर और रोजगार की हकीकत भी आंख खोलने वाली है। भारत में केवल 8 प्रतिशत ग्रेजुएट्स को ही उनकी पढ़ाई के अनुसार नौकरी मिलती है, जबकि ग्रेजुएट युवाओं की बेरोज़गारी दर लगभग 29 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इसका साफ मतलब है कि सिर्फ डिग्री से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती।

यही वजह है कि आज स्किल गैप एक बड़ी समस्या बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 50 प्रतिशत से थोड़े ज्यादा छात्र ही जॉब के लिए तैयार (Employable) माने जाते हैं। बाकी छात्रों में कम्युनिकेशन स्किल, टेक्नोलॉजी नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कमी पाई जाती है। इसलिए अब पढ़ाई के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट बेहद जरूरी हो गया है।

12वीं के बाद करियर चुनते समय छात्रों को अपनी स्ट्रीम के अनुसार विकल्पों को समझना चाहिए।

साइंस स्ट्रीम में मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, डेटा साइंस और रिसर्च जैसे क्षेत्र हैं।

कॉमर्स स्ट्रीम में CA, CS, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बीबीए और एमबीए जैसे मजबूत विकल्प हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में सिविल सर्विस, लॉ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, टीचिंग और डिजाइनिंग जैसे अवसर मौजूद हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग जैसे नए क्षेत्र भी तेजी से उभर रहे हैं।

कई बार छात्र को यह समझ नहीं आता कि वह किस क्षेत्र में जाए। ऐसे में करियर काउंसलिंग बहुत मददगार साबित हो सकती है। करियर काउंसलर छात्र की रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व के आधार पर सही दिशा दिखा सकता है। माता-पिता और शिक्षकों से सलाह लेना भी जरूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय छात्र को खुद लेना चाहिए।

करियर चुनते समय एक और जरूरी बात है - समय और धैर्य। सफलता रातों-रात नहीं मिलती। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना, खुद को अपडेट रखना और असफलताओं से सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में करियर बदलना भी सामान्य बात हो गई है, इसलिए गलत फैसले से घबराने के बजाय उससे सीख लेना ज्यादा जरूरी है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि आज का समय डिग्री का नहीं बल्कि दिशा, स्किल और आत्मविश्वास का है। जो छात्र खुद को पहचान लेता है, सही जानकारी जुटाता है और लगातार मेहनत करता है, वही असली सफलता हासिल करता है।

सही करियर वही है जिसमें केवल पैसा नहीं, बल्कि संतोष, सम्मान और आत्मविश्वास भी मिले।

शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का आगमन, शिव मंदिर पर भव्य स्वागत

सुबह सवेरे सोहागपुर। समीपवर्ती ग्राम करनपुर में देव प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आयोजक समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया के धार्मिक आयोजन में अनंत श्री विभूषित पश्चिमाम्नाय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानन्द सरस्वती जी महाराज का आज आगमन हुआ। विख्यात शिव पार्वती

मंदिर के पास उनका भव्य स्वागत किया गया। शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की अगवानी करके शोभायात्रा निकाली गई।इस शोभायात्रा में केसरिया रंग की साड़ी पहनी कई मातृशक्ति शामिल थीं। इसके अलावा आयोजक समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया सहित नगर एवं ग्राम करनपुर आदि के गणमान्य नागरिक एवं धर्मप्रेमी शामिल थे।ज्ञातव्य है कि समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया ने ग्राम करनपुर में भव्य मंदिर निर्माण कराया है। जिसमें शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में देव प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह संम्पन्न होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिवस 11 फरवरी को ग्राम में प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिक, मातृशक्ति भारी संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ कर रहे हैं। समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया ने क्षेत्र के नागरिकों से देव प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम करनपुर पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग 22 पर स्थित है।

सावधान: चारा काटने गए व्यक्ति की मौत

सुबह सवेरे सोहागपुर। कभी कभी किसान अपने ही खेत की सुरक्षा में रखे तार से अपने ही जीवन अंत हो सकता है। कृषक गण सावधान रहें। ऐसा ही वाकिया सोहागपुर पुलिस थाने के अंतगत ग्राम माछा में घटित हुआ है। जिसमें कमलसिंह लोधी पिता चुन्नीलाल लोधी उम्र 65 साल की चारा काटने निकले कृषक बसंत के खेत पर गए थे। दोपहर 3बजे तक घर वापिस नहीं आने के बाद परिजनों ने उनकी खोजबीन प्रारंभ की। रात्रि करीबन 9बजे कमलसिंह लोधी अचेत अवस्था अवस्था में पड़े थे। उनके दाहिने हाथ में चारा काटने का दांतरा था।जो बाजू में पड़ी बिजली की डोरी से चिपका हुआ था। उनको सोहागपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया। डाक्टर ने कमलसिंह लोधी को मृत होना बताया। उनके पुत्र सुनील लोधी ने उक्त घटना की सोहागपुर पुलिस थाने में जानकारी दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्ट्म के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न न हो, ध्वनि विस्तारक पर रोक: एसडीएम प्रियंका भल्लावी

सुबह सवेरे सोहागपुर। सोहागपुर उपखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल,हायर सेकंडरी की वार्षिक परीक्षा का फरवरी में कार्यक्रम घोषित किया है। अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है ।कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में डी. जे. का उपयोग देर रात्रि तक तेज गति से हो रहा है। इस कारण छात्र,छात्राओं को पढाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के असमय प्रसारण पर रोक लगाना आवश्यक है।अतः उपखण्ड सोहागपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आगामी आदेश तक डी. जे. बजाने पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने की स्थिति पर संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी से लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लिखित अनुमति प्राप्त करें। स्थिति के अनुसार सशर्त अनुमति आदेश ही जारी किए जाएँगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाए। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

पुलिस ने चोरी का माल किया बरामद, आरोपियों को भेजा जेल

सूने मकानों में चोरी करने वाली महिला आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाली महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से चोरी का माल बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी कर आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर 2025 को फरियादी भवानी प्रसाद पिता स्व. गंगाप्रसाद मालवीय, (67) निवासी वार्ड नंबर 10 कृष्णपुरा टिकारी, बैतूल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके सूने मकान से अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोडक़र पुराने इस्तेमाली सोने-चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के, सोने की चेन, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, मोती, चांदी की पायल, करधन, 40 इंच एलजी कंपनी का टीवी एवं अन्य गृहस्थी का सामान चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 01(4), 05(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान चोरी गए माल की लगातार तलाश-पतारसी करते हुए ओझाढाना गंज बैतूल क्षेत्र की संदिग्ध महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया

कि वह कबाड़ बिनते समय टिकारी क्षेत्र में एक मकान पर कई दिनों से ताला लगा देख, 1 अक्टूबर की रात्रि में फरियादी के मकान का ताला तोडक़र चोरी की गई। पुलिस ने आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी कर आरोपियों को जिला जेल भेजा गया।

आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किया सामान- पुलिस ने आरोपी ग्रेशी उर्फ निशा से एलजी कंपनी की एलईडी टीवी, पीतल की परात, घघरी, कुकर, पीतल की कड़ाही, चांदी के 05 सिक्के, सोने जैसी धातु का पेंडल, झालर वाली चांदी की पायल की जोड़ी, आरोपी संजना उर्फ नागिन से डूंताबे का लोटा, पीतल की परात, सोने की अंगूठी, सोने जैसे 06 मोती, चांदी का करधन, चांदी के 04 सिक्के और आरोपी सुनिता उर्फ टकली से मिक्सी, जर्मन की कड़ाही, सोने की अंगूठी, चांदी के 04 सिक्के बरामद किये। इस कार्रवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उनि बसंत अहके, उनि छत्रपाल धुर्वे, प्र.आर. शिवकुमार, प्र.आर. तरुण पटेल, म.प्र.आर. ललिता इवने, आरक्षक उ'जवल दुबे, निर्भया टीम म.आर. 'योति एवं म.आर. व'छला की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस ने हत्या के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

बैतूल। पुलिस ने हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2025 को विवेक पिता भगवान मरकाम, निवासी कालापाठा ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह सागौन बाबा बगिया में पूजा-पाठ करने गया था। उसी दौरान आरोपी अन्नु ठाकुर, अविनाश ठाकुर, आयुष, कपालसिंह, रोहित, जुनैद, कुणाल एवं अन्य साथी उसके पास आए। अन्नु ठाकुर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को धमकाते हुए चाकू दिखाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाया गया तथा चुन्नीढाना के सामने ले जाकर सभी आरोपियों ने एक राय होकर गाली-गलौच करते हुए रॉड एवं पत्थरों से मारपीट की, जिससे फरियादी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय बैतूल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने धारा 415, 296(बी), 115(2), 109(1), 140(1), 191(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2020 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 100(1) बीएनएस का इजाफा किया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुनील लाटा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गंज निरीक्षक नीरज पाल के नेतृत्व में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया।

प्रकरण में पूर्व में आरोपी अन्नु उर्फ अनिकेत पिता कृपालसिंह ठाकुर उम्र 27 वर्ष निवासी चुन्नीवाना, जुनैद उर्फ काला पिता इनायत अली उम्र 18 वर्ष निवासी उमरी, कृपालसिंह ठाकुर पिता शिवलाल सिंह ठाकुर उम्र 62 वर्ष निवासी चुन्नीढाना एवं दो विधि विरुद्ध अपचारी बालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। वहीं 9 फरवरी को फरार आरोपी जतिन उर्फ पासी पिता संदीप रागडे उम्र 19 वर्ष निवासी दुर्गा वार्ड, मुर्गी चौक को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक देवकरण डहेरिया, निरीक्षक नीरज पाल, उप निरीक्षक इरफान कुरैशी, सहायक उप निरीक्षक किशोरीलाल सल्लाम, प्रधान आरक्षक मयुर, प्रधान आरक्षक नीलेश, आरक्षक पवन लौवंशी, आरक्षक गजानंद एवं आरक्षक नरेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।

सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर घूम रहा आरोपी धराया

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चक्कर रोड पेट्रोल पंप के पास हाथ में लोहे का धारदार चाकू लेकर घूम रहा है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को हाथ में लोहे का धारदार चाकू लिए हुए पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सन्नी उर्फ संदीप धुर्वे, पिता स्व. विसराम धुर्वे, उम्र 20 वर्ष, निवासी हिवरखेड़ी बताया। आरोपी के कब्जे से 1 लोहे का धारदार चाकू विधिवत गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

12वीं बोर्ड परीक्षा की शांतिपूर्ण शुरुआत, छह परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी, नकल की कोई शिकायत नहीं

बैतूल/भौंरा। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (12वीं) मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 की शुरुआत मंगलवार 10 फरवरी को शाहपुर विकासखंड में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में हुई। पहले दिन परीक्षा सभी केंद्रों पर समय पर शुरू हुई और बिना किसी बाधा के संपन्न कराई गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शाहपुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष विकासखंड में कुल छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 709 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 701 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 8 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। केंद्र-वार स्थिति पर नजर डालें तो शासकीय संदीपनी विद्यालय, शाहपुर में सभी 171 पंजीकृत परीक्षार्थी उपस्थित रहे और यहां अनुपस्थिति शून्य रही। शासकीय कन्या उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर में 181 में से 179

परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2 अनुपस्थित रहे। शासकीय बालक उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, भौंरा में 174 में से 170 परीक्षार्थी उपस्थित पाए गए और 1 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। शासकीय उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, धपाड़ा में 82 में से 80 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तथा 2 अनुपस्थित रहे। शासकीय उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, बीजादेही में 50 में से 49 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 1 अनुपस्थित पाया गया। इसी तरह शासकीय उ'चतर माध्यमिक विद्यालय, केसिया में 81 में से 79 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षक और उडनदस्ता दल मौजूद रहे। परीक्षा कक्षों में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की जांच, उपस्थिति की पुष्टि और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक पाई गईं। शिक्षा विभाग के अनुसार किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल, अनुचित साधनों के उपयोग या अव्यवस्था की कोई शिकायत सामने नहीं आई। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिससे परीक्षार्थियों को बिना किसी तनाव के परीक्षा देने का अवसर मिला। अधिकारियों ने बताया कि आने वाली परीक्षा तिथियों में भी इसी तरह सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।

भाजपा आजीवन सदस्यता निधि अभियान को मिला नया नेतृत्व

उपेंद्र पाठक संयोजक एवं निलेश चावरिया सहसंयोजक मनोनीत

बैतूल / मुलताई। भाजपा जिला संगठन द्वारा संचालित आजीवन सदस्यता निधि अभियान के अंतर्गत नगर मंडल मुलताई में संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की गई हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार द्वारा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू की सहमति से उपेंद्र पाठक को संयोजक एवं निलेश चावरिया को सहसंयोजक के पद पर मनोनीत किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी रामचरण मालवीय ने बताया कि संगठन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से

यह मनोनयन किया गया है। आजीवन सदस्यता निधि अभियान भाजपा का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभियान है, जिसके माध्यम से पार्टी की वैचारिक मजबूती के साथ-साथ संगठनात्मक संसाधनों का विस्तार किया जाता है। जिला संगठन नेतृत्व ने दोनों पदाधिकारियों को दायित्व सौंपते हुए अपेक्षा व्यक्त की है कि उनके अनुभव, निष्ठा, संगठन के प्रति समर्पण और सक्रिय कार्यशैली से नगर मंडल मुलताई में संगठन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ते हुए संगठन विस्तार को नई दिशा मिलेगी। नवनियुक्त संयोजक उपेंद्र पाठक ने संगठन नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजीवन सदस्यता निधि अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग संगठन से जुड़ सकें। इन नियुक्तियों के बाद नगर मंडल मुलताई के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं ईष्ट-मित्रों द्वारा दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ दी गईं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया तथा संगठन विस्तार को लेकर सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से करें निराकरण : जिपं सीईओ

जिला पंचायत सीईओ ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में कुल 106 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर सभी विभागीय

अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में ग्राम मालीतिपटी निवासी दिनेश हनोते ने अनुग्रह सहायता राशि दिलाए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने श्रम अधिकारी को प्रकरण का तत्काल निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। बैतूल तहसील के ग्राम बगवाड़ निवासी कमला उईके ने संबल कार्ड के तहत सहायता राशि प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने श्रम अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

पीएम आवास की किस्त दिलाए जाने की मांग- जनसुनवाई में बैतूल तहसील के ग्राम बरसाली निवासी किसन यादव ने बैतूल -आमला रोड के अधूरे निर्माण को पूर्ण किए जाने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत सीईओ ने पीडब्ल्यूडी के ईई को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम कतिया कोयलारी निवासी राजेंद्र ने आवेदन के माध्यम से पीएम आवास योजना की किस्त नहीं मिलने की शिकायत की। जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम खेड़ीसावलीगढ़ निवासी नीमा मांडवे ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

संक्षिप्त समाचार

12वीं की छात्रा ने कीटनाशक पीकर जान दी

पिपरिया (निप्र)। सिरसिरी गांव की 18 वर्षीय छात्रा शीतल ने कीटनाशक पी लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह 12वीं की छात्रा थी। घटना शनिवार रात की है। शीतल ने मिर्ची में छिड़काव के लिए रखी कीटनाशक दवा पी ली। परिजन उसे रात 11 बजे शासकीय अस्पताल पिपरिया लाए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शीतल के पिता गुड्डन कहार ने बताया वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने कीटनाशक क्यों पिया, इसका कारण समझ नहीं आ रहा। पिछले साल उनके बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी। घटना की जानकारी रोहित कहार ने स्टेशन रोड थाने में दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। एसआई जीएस ठाकुर ने बताया मामला सांईखेडा थाना क्षेत्र का है। जीरो पर मर्ग कायम कर डायरी सांईखेडा भेजी जाएगी।

बैतूल के खत्री-भैरव ने जीती बैलगाड़ी दौड़

नर्मदापुरम(निप्र)। रामजी बाबा मेले के तहत नर्मदा कॉलेज मैदान में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें करीब 50 बैल जोड़ियों ने हिस्सा लिया। बैतूल जिले के ग्राम मोकामाल के जगदीश यादव की बैल जोड़ी खत्री-भैरव ने 6 सेकंड 55 पॉइंट में दौड़ पूरी कर पहला स्थान पाया। उन्हें 25 हजार का प्रथम पुरस्कार मिला। बैतूल के ही ग्राम रातामाटी के कैलाश पटेल की बैल जोड़ी हीरा-लाल बादशाह ने 6 सेकंड 58 पॉइंट में दौड़ पूरी कर दूसरा स्थान हासिल किया।

आरक्षक जीडी भर्ती वर्ष 2025 के द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा 23 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक

बैतूल (निप्र)। आरक्षक (जी.डी.) एवं आरक्षक (रेडियो) के कुल 7500 पदों पर भर्ती के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित कराई गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 25 जनवरी 2026 को वेबसाइट पर घोषित किया जा चुका है। सफल उम्मीदवार को अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं 800 मीटर दौड़, लम्बी कूद एवं गोला फेंक मध्यप्रदेश के 10 स्थानों पर 23 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से आरंभ होगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार मप्र.कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक प्रवीणता परीक्षा स्थल पर पहुंचे। सभी उम्मीदवारों को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना आवश्यक है। उम्मीदवार को शारीरिक प्रवीणता के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड भोपाल, इंदौर में माउण्टेड ट्रूप डिपार्टमेंट परिसर आरएपीटीसी इन्दौर, जबलपुर में परेड ग्राउंड 6वीं वाहिनी विसबल रांझी जबलपुर, ग्वालियर में परेड ग्राउंड 14 वीं वाहिनी विसबल कम्पू ग्वालियर , उज्जैन में महानंदा एरीना ग्राउंड देवास रोड उज्जैन, सागर में शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बहेरिया सागर, रीवा में परेड ग्राउंड 9वीं वाहिनी विसबल रीवा, बालाघाट में फुटबॉल/हॉकी ग्राउंड 36वीं वाहिनी विसबल बालाघाट, रतलाम में भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस स्टैण्ड के पास जावरा रतलाम तथा मुरैना में परेड ग्राउंड 05वीं वाहिनी विसबल मुरैना में आयोजित होगी। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में आधार ई-केवायसी सत्यापन कराया जाएगा। अतः: अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार नम्बर उनके द्वारा लॉक न कर दिया गया हो। दस्तावेज परीक्षण हेतु उम्मीदवारों को समस्त मूल आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रति साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है।

कलेक्टर ने कृषक रथ के भ्रमण कार्यों का जायजा लिया

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज जिले में जारी कृषक रथ भ्रमण व इस दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा दी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों तथा किसानों की जिज्ञासाओं के समाधान हेतु की गई पहल तथा जिले में क्या क्या नवाचारों के माध्यम से किसानों व सहयोगी अन्य पूरकों की लाभ वृद्धि में कैसे बढ़ावा करें तथा भ्रमण के दौरान क्या क्या प्रमुख समस्याएं संज्ञान में आई इत्यादि की जानकारी प्राप्त की है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि किसान रथ भ्रमण गांवों में सभी विभागों की योजनाओ की जानकारी गांव वालों को हो ऐसे सफल प्रयास प्रशिक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है तब तक उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जायेगा।

आत्मनिर्भर व विकसित भारत 2047 के संकल्पों को साकार करने वाला है केंद्रीय बजट : मंत्री श्री सारंग

बजट में गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता के साथ हर वर्ग के कल्याण को दी गई है प्राथमिकता

सीहोर (सीहोर में आयोजित पत्रकार वार्ता में युवा, खेल एवं सहकारिता मंत्री श्री कैलाश विश्वास सारंग ने केंद्रीय बजट 2026 - 27 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया केन्द्रीय बजट विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह बजट सतत् आर्थिक विकास के साथ जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए गये है। यह बजट सभी वर्गों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा। उन्होने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत के विजन का सशक्त दस्तावेज़ है। गरीब, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता के साथ मध्यम वर्ग और उद्यमियों के कल्याण व सशक्तिकरण के प्रावधान बजट में किए गए हैं। जो मध्यप्रदेश सहित देश को 2047 के विकसित भारत की ओर मजबूती से ले जाएगा। देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 56 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत तक लाने की भी योजना है। बजट में 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण और 12.2 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए निवेश राशि को 22,500 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यप्रदेश को भी व्यापक लाभ होगा और यह बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बजट 2026-27 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान समृद्धि को मजबूती देने के लिए पशुपालन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यह किसानों की कुल आय का लगभग 16 प्रतिशत है। इस हेतु पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना शुरू किए जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है, साथ ही वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने की घोषणा की है। बजट 2026-27 में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एकीकृत कर मछली पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि ने कहा कि हमारी सरकार की मंशानुसार महिला सशक्तिकरण के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव है, इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छात्राओं को सुरक्षित आवास मिल सकेगा। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं और 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए विशेष पहल की गई है, जिसमें लखपति दीदी योजना पर आधारित सामुदायिक स्व-सहायता समूह उद्यम स्थापित करने का प्रावधान है। लखपति दीदी योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू हुई इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। योजना के तहत महिलाओं को आजीविका से बढ़ाकर बिजनेसवुमन बनाने की ओर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए बजट में व्यापक अवसर हैं। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति का गठन और 15,000 माध्यमिक विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। पर्यटन क्षेत्र में आई.आई.एम. के सहयोग से 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा। एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमियों को संबल प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 5 सालों में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स को जोड़ा जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।

18 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 3989 छात्र हुए शामिल

बैतूल (निप्र)। सत्र 2026-27 के लिए जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल एवं श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।परीक्षा के लिए 4296 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3989 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 307 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल श्री भूपेन्द्र वरकड़े ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं, दिशा-निर्देशों के पालन एवं अनुशासन की स्थिति का जायजा लिया। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन पर संबंधित केंद्राध्यक्षों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों की प्रशंसा की गई।

निवेश के लिए दी जमीन से माफिया निकाल रहे मिट्टी

औद्योगिक क्षेत्र के फेस-टू में अवैध उत्खनन जारी, कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा हौसला

नर्मदापुरम(निप्र)। नर्मदापुरम के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में सरकार जहां निवेश बढ़ाने और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों को सस्ती जमीन दे रही है, वहीं उसी जमीन से मिट्टी का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। माफिया खुलेआम खुदाई कर मिट्टी का परिवहन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है।

फेस-टू में चल रहा काम

सूत्रों के मुताबिक अवैध उत्खनन औद्योगिक क्षेत्र के फेस-टू में हो रहा है। यहां कंपनियों को प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित की जानी है। आरोप है कि प्लॉट विकसित होने से पहले ही माफिया जमीन को खोखला कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से उनका हौसला बढ़ गया है। यही वजह है कि उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा।

पहले भी सामने आ चुका मामला

मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन का यह पहला मामला नहीं है। करीब डेढ़ महीने पहले फेस-वन के प्लॉट नंबर 18 से बड़े पैमाने पर मिट्टी चोरी का मामला सामने आया था। तब माफिया करीब 12 हजार 683 घनमीटर मिट्टी, यानी एक हजार से ज्यादा डंपर भरकर ले गए थे। सूत्रों का दावा है कि यह मिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में ही स्थापित और निर्माणाधीन कुछ बड़ी कंपनियों में डाली गई।

अफसरों के बयान

एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक महेंद्र वर्मा ने कहा कि उन्हें अवैध उत्खनन की जानकारी नहीं है। वे स्टाफ को भेजकर मौके की जांच करवाएंगे। वहीं तहसीलदार महेंद्र चौहान ने बताया कि वे चौरागढ़ मेले में ड्यूटी पर हैं, जांच के लिए आरआई और पटवारी को भेजा जाएगा। जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम से संपर्क नहीं हो सका।

मामला उजागर होने पर खुली नींद

जब यह मामला मीडिया में सामने आया, तब प्रशासन हरकत में आया। जिला खनिज अधिकारी, एसडीएम, नायब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे और खुदाई वाली जगह की नपती कराई। नपती में अवैध उत्खनन की पुष्टि तो हुई, लेकिन पंचनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मिट्टी किसने खोदी, कहां ले जाई गई और उसका उपयोग कहां हुआ।

दूसरी बार बनाना पड़ा पंचनामा

इसके बाद संयुक्त टीम को दोबारा मौके पर पहुंचकर नया पंचनामा तैयार करना पड़ा। बाद में खनिज विभाग ने देरी से अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाकर अपर कलेक्टर के पास भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि फेस-टू में जमीनों की रजिस्ट्री का काम जारी है और आगे प्लॉट काटे जाने हैं। इससे पहले ही बिजली ग्रिड के आसपास बिना अनुमति मिट्टी खोदकर ले जाई जा रही है।

पचमढ़ी के महादेव मेले में श्रद्धालुओं की लंबी कतार

भारी-भरकम त्रिशूल लेकर चौरागढ़ पहुंचे भक्त

पिपरिया(निप्र)। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में आयोजित महादेव मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले इस मेले में महाराष्ट्र और विदर्भ सहित देश के कोने-कोने से भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चौरागढ़ की पहाड़ियों पर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है और हजारों श्रद्धालु कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

मन्नत के त्रिशूल लेकर चढ़ रहे पहाड़ : मेले में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर लोहे के भारी-भरकम त्रिशूल लेकर पैदल ही दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। रविवार को भी हजारों भक्त आस्था के इन त्रिशूलों को कंधे पर उठाए चौरागढ़ मंदिर पहुंचे। महादेव मंदिर से लेकर चौरागढ़ की चोटी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो कड़ाके की ठंड और दुर्गम रास्ते की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे हैं।

अधिकारियों ने पैदल चलकर जांची व्यवस्था : कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देश पर पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। एसडीएम आकिब खान ने पैदल ही चौरागढ़ मंदिर तक का सफर तय किया और रास्ते में सुरक्षा व चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए कि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा और मेडिकल टीम : तहसीलदार वैभव बैरागी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील रास्तों पर तैनात किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां सेक्टर प्रभारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। श्रद्धालुओं की अचानक तबीयत बिगड़ने या चोट लगने की स्थिति में विभिन्न पॉइंट्स पर मेडिकल टीमें दवाओं के साथ मौजूद हैं।

पिपरिया में मिली मृत महिला 4 महीने की गर्भवती थी:पोस्टमार्टम में खुलासा

पिपरिया (निप्र)। पिपरिया के डोकरीखेड़ा डैम के पास जंगल में शनिवार को मिली महिला की मौत को लेकर पोस्टमार्टम में अहम खुलासा हुआ है। रविवार को हुए पीएम में सामने आया कि मृतका चार माह की गर्भवती थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पिपरिया अस्पताल में प्रथम श्रेणी महिला चिकित्सक डॉक्टर अनीता साहू और डॉक्टर एसपी सिंह ने शव का पोस्टमार्टम किया। डॉ. साहू ने बताया कि महिला 4 माह की गर्भवती थी और चेहरे पर दो गहरी चोटें थीं, जो किसी कठोर वस्तु से लगने जैसी प्रतीत होती हैं। एफएसएल अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने जांच के लिए नमूने लिए। पुलिस के अनुसार शव काफी सड़ा-गला हुआ था। जांच के लिए बिसरा, डीएनए और स्लाइड बनाकर लैब भेजी गई हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। थाना प्रभारी आदित्य सैन ने बताया कि महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। सभी थानों को सूचना भेजकर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सीएचसी नटेरन में सीएमएचओ ने की स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा

फील्ड स्टाफ को दिए सुधार के निर्देश

विदिशा (निप्र)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नटेरन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामहित कुमार द्वारा गत दिवस स्वास्थ्य कार्यक्रमों की अघतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) एवं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान सीएमएचओ ने सीएचओ, एमपीडब्ल्यू, एमपीएस तथा एएनएम स्टाफ के कार्यों का बिंदुवार मूल्यांकन किया। उन्होंने यू-विन पोर्टल पर रियल टाइम एंट्री, एचआरपीडब्ल्यू (हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन) की पहचान, एएनसी पंजीकरण, अनुमानित प्रसव तिथि की सही दर्जीकरण तथा 4 एएनसी चेकअप की शत-प्रतिशत पूर्ति पर विशेष जोर दिया।

सीएमएचओ ने कहा कि गर्भवती माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में चिन्हित गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें तथा निर्धारित जांचें पूर्ण कराएं। आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण और उपचार लाभ की स्थिति पर चर्चा करते हुए सीएमएचओ ने लक्ष्य पूर्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में एचबीएनसी (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर) अंतर्गत सात फरवरी 2026 की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई। नवजात शिशुओं के घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और फॉलोअप में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

सीएमएचओ ने उपस्थित स्टाफ को निर्देशित किया कि सभी डेटा की एंट्री समय पर और सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज की जाए, जिससे शासन स्तर पर योजनाओं की वास्तविक प्रगति प्रदर्शित हो सके। अंत में बीएमओ और बीपीएम को मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने, फील्ड विजिट बढ़ाने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम — स्वच्छ ऊर्जा, समृद्ध किसान की दिशा में प्रभावी पहल

सीहोर (निप्र)। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित 'नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने तथा गोबर एवं जैविक अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर शासकीय अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस जैसी स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद भी प्राप्त होती है। योजना पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की लागत कम कर आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीहोर जिले के ग्राम बिलकिसगंज निवासी किसान श्री अजब सिंह मेवाड़ा भी उन किसानों मे से एक हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। किसान श्री मेवाड़ा ने योजना के अंतर्गत 03 घनमीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र स्थापित कराया, जिसके लिए उन्हें शासन की ओर से 14,350 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। संयंत्र स्थापित होने के बाद उनके परिवार को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में बायोगैस उपलब्ध हो रही है, जिसका उपयोग वे अपने रसोईघर में भोजन बनाने के लिए कर रहे हैं। अब उन्हें गैस सिलेंडर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, जिससे घरेलू खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है और ईंधन की समस्या से भी राहत मिली है।

संयंत्र से निकलने वाली स्लरी का उपयोग श्री मेवाड़ा जैविक खाद के रूप में अपने खेतों में कर रहे हैं। इस खाद के उपयोग से खेतों की उर्वरता में सुधार हुआ है, खरपतवार की समस्या कम हुई है तथा फसल उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटने से खेती की लागत कम हुई है और भूमि की गुणवत्ता में सुधार आया है। इस प्रकार नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम किसानों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता, जैविक खेती और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

गांधी मेडिकल की एमबीबीएस छात्रा का शव बाथरूम में मिला, पास ही पड़ी थी एसिड बॉटल

4 महीने पहले एडमिशन लिया था

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा रोशनी का शव बाथरूम में पड़ा था। पास ही एसिड की बोतल भी मिली है। रोशनी ने पिछले साल ही अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। जानकारी के मुताबिक, रोशनी डे-स्कॉलर थी और कोहेफिजा थाना क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। जब वह सुबह कॉलेज के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे बुलाने के लिए पहुंचे।

जवाब नहीं मिला तो तोड़ा दरवाजा- छात्राओं के मुताबिक, रोशनी को कई बार आवाज दी। उसे फोन कॉल किया, लेकिन रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीजी के गार्ड को सूचना दी। गार्ड पहुंचा तो पहले कमरे और फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया, जहां रोशनी पड़ी मिली।

पास में मिली संदिग्ध बोतल- स्टूडेंट्स ने बताया कि रोशनी के पास एक खाली एसिड की बोतल भी पड़ी हुई थी। फौरन कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी गई। रोशनी को सुबह करीब 8:30 बजे हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग ले जाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

आलीराजपुर की थी, पिछले हफ्ते ही भोपाल लौटी थी- रोशनी आलीराजपुर की रहने वाली थी। साथी छात्रों ने बताया कि वह पिछले हफ्ते ही घर से लौटकर भोपाल आई थी। वह पढ़ाई को लेकर गंभीर और शांत स्वभाव की थी।

डीन ने कहा- पढ़ाई को लेकर टेंशन में थी रोशनी- गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन कविता एन. सिंह ने बताया कि रोशनी के मोबाइल में परिजन को भेजे गए मैसेज से पता चला है कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। मेहनत करने के बावजूद ठीक से समझ नहीं पा रही थी।

पोस्टमॉर्टम के बाद सामने आएगी मौत की वजह- फिलहाल रोशनी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भोपाल के मसूरी क्षेत्र स्थित मॉर्चुरी भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दे दी है। घटना को लेकर कोहेफिजा पुलिस जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

भोपाल मेट्रो रूट पर अब उत्तर विधायक की आपत्ति

कहा- शाही कब्रिस्तान से न गुजरे मेट्रो; रूट में बदलाव करें

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मेट्रो के ऑरेंज लाइन के फेज-2 के रूट पर अब उत्तर विधायक आतिफ अकील ने आपत्ति उठाई है। भोपाल टॉकीज के पास स्थित शाही कब्रिस्तान में से अंडरग्राउंड रूट निकलने पर विधायक अकील ने मेट्रो कॉरपोरेशन के अफसरों से कहा कि क्या मेट्रो के लिए कब्रिस्तान में ही जगह मिली है? यहां हमारे बाप-दादा दफन है। कई कब्र हैं। इसलिए कब्रिस्तान में से मेट्रो कतई न गुजरे।

विधायक अकील ने बताया कि मेट्रो भोपाल टॉकीज स्थित शाही कब्रिस्तान से होकर न गुजरे, इसके लिए शाही वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में केस लगाया था। जिसमें उन्हें स्टे मिला हुआ है। इस स्टे की आगे की सुनवाई के लिए न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष बैठकर बात कर लें।

इसी सिलसिले में सोमवार को मीटिंग और निरीक्षण किया गया। इस दौरान अफसरों से कहा कि कब्रिस्तानों में से मेट्रो के कार्य को हटाया जाए। इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। इस दौरान मप्र वक्फ बोर्ड के सदस्य हसन जैदी, सदस्य आजम खान एवं मेट्रो अफसर मौजूद थे।

विधायक आतिफ अकील ने कहा कि कब्रिस्तान में से किसी भी हालत में मेट्रो नहीं गुजरेगी। मेट्रो कॉरपोरेशन को रूट बदलना चाहिए।

यह है मेट्रो का फेज-2- बता दें कि 21 दिसंबर से भोपाल में ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाषनगर से एम्स के बीच मेट्रो दौड़ने लगी है। अब दूसरे फेज के रूट यानी, सुभाषनगर से करोंद तक का काम चल रहा है। इसकी कुल लंबाई 16.74 किमी है।

दूसरे फेस में सुभाषनगर से करोंद की कुल दूरी 9.74 किमी लंबा है, लेकिन 8.77 किमी में होगा। इसमें से 5.38 किमी हिस्से में 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिस पर 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस काम की शुरुआत हो चुकी है। पुल बोगदा, ऐशबाग, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला, कृषि उपज मंडी और करोंद चौराहा पर स्टेशन बनेंगे। वहीं, बाकी 3.39 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 मेट्रो स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन व नादरा बस स्टैंड भी रहेंगे। यह पूरा काम 890 करोड़ रुपए में होगा। इसी रूट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

भोपाल में ब्लू लाइन के रूट को अंडरग्राउंड करने की मांग- इससे पहले सांसद आलोक शर्मा भदभदा से रत्नागिरी तक मेट्रो के ब्लू लाइन प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता चुके हैं। यातायात सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने कहा था कि भारत माता चौराहे से लिली टॉकीज चौराहे तक मेट्रो का रूट अंडरग्राउंड हो। विधायक भगवानदास सबनानी ने भी सहमति जताई थी। हालांकि, इस रूट पर काम पिछले 7 महीने से चल रहा है। पिलर भी बनने शुरू हो गए हैं। पूरा रूट एलिवेटेड है। बाद में मेट्रो कॉरपोरेशन ने इस मांग को खारिज भी कर दिया था।

बर्फ पिघलने से प्रदेश में आएंगी सर्द हवाएं, ठिठुरन बढ़ेगी

अगले 2 दिन तेज ठंड नहीं, 3-4 डिग्री बढ़ेगा टेम्प्रेचर, ग्वालियर-चंबल में ज्यादा असर

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज ठंड नहीं पड़ेगी। इससे टेम्प्रेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पहाड़ों से जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) गुजर जाएगा और बर्फ पिघलेगी तो प्रदेश में सर्द हवाएं फिर से ठिठुरन बढ़ाएगी। मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे की माने तो पूरे फरवरी महीने मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। वहीं, पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है। इस वजह से प्रदेश में अगले 2 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्से में सोमवार को दिन में तेज धूप खिली रही। इससे अधिकतम तापमान में बढ़ा हुआ रहा। हालांकि, रात व अलसुबह ठंड का असर बरकरार रहेगा। पारे में जरूर बढ़ोतरी होगी।

इसलिए बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक पांडे ने बताया, सिस्टम गुजरने और बर्फ पिघलने के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। 13, 14 और 15 फरवरी को तापमान में गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ जाएगी। उत्तर से ठंडी हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा।

13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, कटनी का करौंदी सबसे ठंडा- रविवार-सोमवार की रात में प्रदेश के 13 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। प्रदेश का सबसे ठंडा कटनी का करौंदी रहा। यहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर-खजुराहो में 6.4 डिग्री, पचमढ़ी में 7.4 डिग्री, अमरकंटक में 7.8 डिग्री, दतिया में 8.1 डिग्री, रीवा में 8.3 डिग्री, राजगढ़ में 8.6 डिग्री, उमरिया में 8.8 डिग्री, शिवपुरी में 9 डिग्री, मंडला में 9.4 डिग्री, मलाजखंड में 9.5 डिग्री और नौगांव में पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पांच बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में सबसे कम 10.2 डिग्री, इंदौर में 11.2 डिग्री, ग्वालियर में 10.6 डिग्री, उज्जैन में 12.4 डिग्री और जबलपुर में 11.4 डिग्री दर्ज किया गया।

अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम

11 फरवरी- अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिन में तेज धूप खिली रहेगी।

12 फरवरी- तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। रात और अलसुबह ही ठंड का असर रहेगा।

बजट प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का रखा गया है ध्यान: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के समक्ष वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों का हुआ प्रेजेंटेशन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट प्रस्तावों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बताते हुए उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा के दृष्टिकोण तथा प्रस्ताव तैयार करने में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्रालय में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव (वित्त) श्री मनीष रस्तोगी तथा वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्रि-परिषद के समक्ष भी आज ही बजट प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन हुआ। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित बजट 18 फरवरी को उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

भोपाल में नया अजूबा... हाईटेंशन पोल के नीचे निकली सड़क

- 90 डिग्री ब्रिज के बाद एफिल टावर सड़क; कई साल से बना खतरा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज और ठिगने मेट्रो स्टेशन के बाद एक और नया अजूबा सामने आया है। राजधानी के करोंद इलाके में हाईटेंशन लाइन के टावर (पोल) के नीचे से सड़क निकाल दी गई, जो किसी 'एफिल टॉवर' सड़क की तरह है। मामला सामने आने के बाद अब यह पोल सुर्खियां बंटोर रहा है।

करोंद की विनायक कॉलोनी में कई साल से हाईटेंशन का पोल एफिल टॉवर जैसा खड़ा है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इसके नीचे से ही सड़क भी निकाल दी गई। लोग पैदल चलने के साथ अपनी कार और मोटरसाइकिलों से आना-जाना भी करते हैं। ऐसे में हाईटेंशन लाइन के चपेट में आने का डर बना रहता है।

बारिश में करंट फैलने का डर- रहवासियों ने बताया कि टावर के नीचे से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। दूसरी ओर, बारिश के दिनों में करंट फैलने का डर रहता है। भोपाल राजधानी है, सरकार को हाईटेंशन लाइन और टावर को लेकर ध्यान देना चाहिए। दोनों को ही शिफ्ट किया जाना चाहिए।

बिजली कंपनी हटाने के प्रयास में जुटी- दूसरी ओर, बिजली कंपनी भी इस टावर को अन्य जगह शिफ्ट करने में लगी है। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये टावर और हाईटेंशन लाइन नहीं हट पाई। सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह टावर फिर से सुर्खियों में आ गया है।

कई साल से खड़ा

करोंद के महेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह पोल उन्हीं के वार्ड में हैं, जिसे वे कई साल से देखते आ रहे हैं। पहले आसपास रहवासी इलाका नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे आबादी बसने लगी। वर्तमान में अच्छी आबादी यहां रहती हैं। इस तरह खतरा बढ़ गया है।

इंदौर में नहीं थम रहा दूषित पानी का कहर

इंदौर (नप्र)। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से दो और मौत हुई हैं। 75 साल के बुजुर्ग शालिग्राम ठाकुर की सोमवार रात और दो साल की बच्ची रिया की मौत मंगलवार को सुबह हुई। गंदे पानी से अब तक कुल 35 लोगों की जान जा चुकी है।

शालिग्राम की बेटी मोना बघेल ने बताया कि 2 जनवरी को उलटी-दस्त के कारण शेल्बी हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। वहां से उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसके बाद वे वेंटिलेटर पर ही थे। करीब 12 दिन पहले उन्हें डिस्चार्ज किया गया था।

बच्ची और बुजुर्ग की मौत, मौतों की संख्या 35 हुई

परिजन का कहना है कि 18 साल पहले उन्हें लकवा हुआ था। इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं थी। उधर, बॉम्बे हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर राहुल पाराशर ने बताया कि मरीज को शुरू से ही कार्डियक की तकलीफ थी। वहीं, दो साल की बच्ची रिया पिता सूरज प्रजापति की मंगलवार सुबह 4.30 बजे मौत हुई। 27 दिसंबर को उलटी-दस्त के कारण परिजन ने उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाया था। इसके बाद हालत ठीक हुई, लेकिन बाद में फिर बिगड़ती गई।

बच्ची के लिवर में तकलीफ बताई गई थी- 15 दिन पहले रिया को चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट किया गया था। यहां उसके लिवर में तकलीफ बताई गई थी। इसके बाद उसे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां करीब 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि

दूषित पानी के कारण ही तबीयत बिगड़ी। उसका असर लिवर तक हुआ।

रीवा में फेसबुक फ्रेंड ने नाबालिग से किया रेप

17 साल की लड़की ने मृत बच्चे को दिया जन्म; शादी का झांसा देकर तोड़ा भरोसा

रीवा (नप्र)। रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने मृत नवजात को जन्म दिया है। मामला फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद दुष्कर्म का है। पीड़िता को बीती रात परिजनों ने अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती कराया था। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर सगरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि नाबालिग की पहचान एक युवक से फेसबुक के जरिए हुई थी। ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों की मुलाकातें होने लगीं। इसी दौरान आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर आरोपी ने बातचीत बंद कर दी और संपर्क तोड़ लिया।

लोक-लाज के कारण चुप रहे परिजन- लोक-लाज और सामाजिक दबाव के चलते पीड़िता और उसके परिजन लंबे समय तक चुप रहे। समय पर इलाज और जानकारी न मिलने के कारण मामला गंभीर हो गया। देर रात प्रसव के दौरान उसने मृत बच्चे को जन्म दिया।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने श्रीलंका में हंबनटोटा (श्रीलंका) में भारत के महावाणिज्य दूत श्री हरविंदर सिंह एवं अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री चोवना मीन के साथ गाले डच फोर्ट का भ्रमण किया।

खंडवा में एआई से पति का चाची संग बनाया फोटो

ब्वॉयफ्रेंड के मोबाइल में मिले 10 फर्जी अकाउंट

खंडवा (नप्र)। खंडवा में एक महिला को एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरों के जरिए बदनाम करने और 50 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले की आरोपी महिला के परिवार की ही बहू निकली। पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

आरोपी महिला ने अपने पति और उसकी चाची की सोशल मीडिया से तस्वीरें उठाईं और उन्हें एआई तकनीक से अश्लील रूप में बदल दिया। इसके बाद इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर विधवा महिला से 50 हजार रुपये ऐंठ लिए।

आरोपी पत्नी पति को छोड़ ब्वॉयफ्रेंड के साथ रह रही- पुलिस जांच में सामने आया कि, आरोपी महिला राखी कपाड़िया भोपाल में अपने ब्वॉयफ्रेंड शाहरूख के साथ रहती है। उसने पति सुदामा को छोड़ दिया हैं। राखी को शक था कि उसके पति का उसकी विधवा चाची के साथ अफेयर हैं। चाची को बदनाम करने के लिए उसने सोशल मीडिया से पति और चाची के फोटो निकाले। इसके बाद उन तस्वीरों को एआई

के जरिए अश्लील रूप दिया। फिर सारे रिश्तेदारों को फोटो शेयर कर दिए। रिश्तेदारी में बदनामी हुई तो विधवा चाची ने पुलिस से शिकायत की।

फर्जी अकाउंट से वायरल किए, फिर पैसे ऐंठे- खास बात यह है कि, एआई आधारित अश्लील फोटो वायरल होने के बाद विधवा चाची ने पुलिस से शिकायत की, तब तक यह सामने नहीं आया कि इस कृत्य के पीछे कौन है। जिस सोशल मीडिया अकाउंट से विधवा चाची को ब्लैकमेल करके 50 हजार रूपए लिए गए, वह फर्जी था। पुलिस और सायबर सेल की टीम ने आईपी एड्रेस सर्च कर जांच की तो पता चला कि यह अकाउंट किसी शाहरूख नाम के मोबाइल से भोपाल में बैठी एक महिला ऑपरेट कर रही है।